WWW.Kanchanujala.in

हिन्दी दैनिक

kanchanujala14@gmail.com

कंचन उजाला

लखनऊ से प्रकाशित

सच्चाई के साथ

निया शर्मा से लेकर शिविन नारंग तक इन सितारों ने बिग बॉस 14 का ऑफर ठुकराया

वर्षः 01 अंक : 261 | लखनऊ, गुरुवार, 10 सितम्बर, 2020 | पृष्ठ- 6 | मूल्य - 1 रुपये

वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी)

जीएसटी की भारी चोरी में लिप्त है कैटरिंग व्यवसाई

● आयकर की चोरी ● हाउस टैक्स की चोरी ● विद्युत की चोरी ● घरेलू गैस सिलेंडरो का व्यापारिक उपयोग ● पूर्व आई ए एस संजय गुप्ता के भारी काले धन को ठिकाने लगाता कैटरिंग व्यवसायी

महेंद्र कुमार यादव/विशेष संवाददाता

लखनऊ, कंचन उजाला ब्यूरो। हमारे देश में टैक्स चोरी एक गंभीर समस्या है केंद्र या राज्य में कोई सरकार हो परंतु टैक्स चोर अपने मंसूबे में कामयाब रहते हैं लेकिन जब फसते है तो उनकी संपत्ति तक नीलाम कर के टैक्स की वसूली की जाती है वसूले गएँ टैक्स के राजस्व की आय से ही देश में राज्यों की अर्थव्यवस्था चल रही है जबकि सरकार द्वारा समय-समय पर व्यापारियों व जनता की समस्याओं को देखते हुए करो के ढांचे में संशोधन भी किए जाते हैं देश में 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया और उसमें समय-समय पर 650 से अधिक संशोधन भी किए गए लेकिन कुछ व्यवसाई ऐसे हैं जो जीएसटी तो वसूल रहे हैं और विभाग में जमा नहीं करा रहे हैं अर्थात भारी कर की चोरी कर रहे हैं विडंबना यह है कि टैक्स की चोरी में ये अव्वल है और बहुत ही कम क्रेटरिंग व्यवसायी ऐसे हैं जो ईमानदारी से कर जमा करा रहे हैं सूत्रों के अनुसार प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित यूको बैंक अशोक मार्ग शाखा के सामने स्थित राजकुमार गुप्ता का कैटरिंग का व्यवसाय है और 3 दुकाने किराए पर लेकर जो नगरनिगम के अंतर्गत आती हैं उसमें खाने का रेस्टोरेंट चलाया जाता है जिसका प्रबंधन उसके पुत्र विनोद गुप्ता करते हैं। राजकुमार गुप्ता का आरके कैटरर्स के नाम से कैटरिंग व्यवसाय की फर्म है जिसका पता 1/503 विनय खंड गोमती नगर है जहां भी समस्त व्यवसायिक गतिविधियां चलती है शहर में सभी छोटे-बड़े शादी विवाह के मंडप लानों में इनको पार्टियों के खानों व सर्विसिंग के बड़े आर्डर मिलते हैं जो लाखों में होते हैं जिसके सापेक्ष उनके द्वारा जीएसटी नहीं जमा कराया जाता और पूरे वर्ष में बहुत कम जमा कराया जाता तो यह धन राशि नगण्य रहती है जबकि कैटरिंग व्यवसाय पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है।

राजकुमार गुप्ता का आलम यह है कि प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर कैटरिंग का आर्डर संबंधित पार्टी से ले लेते हैं जिसका प्रबंधन उनका सुपुत्र विनोद गुप्ता करते हैं इनके पास एक छोटी ट्रक भी है जिस पर समस्त वेटर वारदाना सहित संबंधित जिले को कूच कर जाते हैं कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने सरकार को जीएसटी कर हो या पहले सर्विस टैक्स रहा हूं टैक्स चोरी करके भारी चूना लगाया है तथा आश्चर्यजनक पहलू यह है कि कुछ वर्षों पूर्व राजकुमार गुप्ता स्वयं वेटर थे जो विदित है और आज करोड़ों की संपदा के मालिक हैं लखनऊ में बिहार में कई आलीशान मकान वह बड़े बड़े भूखंड हैं सूत्रों के अनुसार अभी गत वर्ष उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण फूड विभाग द्वारा उनके हजरतगंज स्थित रेस्टोरेंट में छापे की कार्रवाई की गई थी और खाने के नमूने पैक किए गए थे जिसकी जांच में सभी नमूने मापदंडों के विपरीत पाए गए जिस पर विभाग द्वारा इन के

खिलाफ अपराधिक मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था जिस केस में राजकुमार गुप्ता जमानत पर है और मुकदमा लंबित चल रहा है सूत्रों के अनुसार राजकुमार गुप्ता की फर्म आरके कैटरर्स धड़ल्ले से आम जनता के उपयोग वाले लाल सिलेंडरों का इस्तेमाल कर रही है जबकि व्यवसायिक उपयोग में नीले सिलेंडर आते हैं यह कानूनन अपराध है उनके यहां रोजाना एक लाल सिलेंडर की खपत सिर्फ हजरतगंज रेस्टोरेंट में होती है पार्टियों में होने वाली खपत अलग है।

एडीएम खाद्य द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और गत वर्षों म ` ` आपने कितने लाल सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जो कि पूर्णतया वर्जित है उसकी जांच की जानी चाहिए और इन के ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत किया जाना चाहिए सबसे रोचक तथ्य यह है कि विभाग को यह भी देखना चाहिए कि इनके द्वारा कितने नीले सिलेंडर क्रय किए गए हैं और तो और इनकी हजरतगंज स्थित रेस्टोरेंट पर सेफ्टी मेजर का प्रयोग न करने के कारण लाल वाला घरेलू सिलेंडर गत माह फट गया था और इनका एक कर्मचारी उसमें गंभीर रूप से घायल भी हो गया था राजकुमार गुप्ता द्वारा किसी तरह इस मामले को रफा-दफा किया गया चर्चाओं के अनुसार राजकुमार गुप्ता के काले कारनामों पर पर्दा डालने हेतु उनके रिश्तेदार व पूर्व आईएएस संजय गुप्ता पुरजोर मदद करते हैं संजय गुप्ता गुजरात कैडर के आईएएस रहे हैं तथा उन्होंने आईएस की सेवा से स्वैच्छिक अवकाश वीआरएस ले लिया है जिनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच प्रवर्तन निदेशालय नई दिल्ली द्वारा की जा रही है जो वर्तमान में चंद्रलोक कॉलोनी अलीगंज लखनऊ में निवास करते हैं राजकुमार गुप्ता बड़े गर्व से सबसे बताते हैं कि संजय गुप्ता की हैसियत कम से कम 20000 करोड़ है वह श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो संजय गुप्ता उनके साथ कार्यरत थे और अपने स्वभाव के कारण वह मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं करते थे और उनकी फाइल को भी फेंक दिया करते थे ऐसा राजकुमार गुप्ता बताते हैं बताया जाता है कि पूर्व आईएएस संजय गुप्ता ने अपनी काफी बेनामी संपत्ति राजकुमार गुप्ता व उनकी पत्नी निर्मला गुप्ता व उनके पुत्र विनोद गुप्ता तथा अन्य पुत्रों के नाम से करा कर रखी है। जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी नई दिल्ली द्वारा की जानी चाहिए इतने कम समय के अंतराल में राजकुमार गुप्ता कैसे इतनी अकूत संपदा का मालिक बन बैठा यह एक रोचक पहलू है राजकुमार गुप्ता की ज्यादातर संपत्तियां उसकी पत्नी निर्मला गुप्ता व विनोद गुप्ता व अन्य पुत्रों के नाम से है।

इन संपत्तियों पर कमर्शियल गतिविधि जारी है चाहे वह उनका निवास 1/ 503 विनय खंड गोमती नगर लखनऊ हो वह खरगापुर पुलिस चौकी गोमती नगर के सामने स्थित भव्य कई हजार स्क्वायर फुट में निर्मित 5 मंजिला कोठी हो या 124 नवल किशोर रोड हजरतगंज लखनऊ स्थित मकान हो सभी जगह कमर्शल गतिविधियां दस्तूर जारी है जिन पर घरेलू विद्युत कनेक्शन इस्तेमाल किया जाता है जो कानूनन जुर्म है विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से भारी विद्युत की चोरी की जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार को चूना लगाया जा रहा है विद्युत विभाग के सतर्कता विभाग को जांच करना चाहिए तथा नगरनिगम को भी उनसे कमर्शियल दर से हाउस टैक्स कर वसूलना चाहिए और कई वर्षों से उनके द्वारा की जा रही कमर्शियल गतिविधियों का संज्ञान लेकर उन पर कमर्शियल कर की वसूली की जानी चाहिए बताया जाता है कि 124 नवल किशोर रोड लखनऊ जिस की मालकिन निर्मला गुप्ता है जो राजकुमार गुप्ता की पत्नी है कुछ वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। जिस की रजिस्ट्री बहुत कम दर पर हुई थी बताया जाता है कि उसमें पूर्व आईएएस संजय गुप्ता का काला धन लगा हुआ है अतः प्रवर्तन निदेशालय को इसकी भी जांच करनी चाहिए कि इतने कम धन राशि मे इस बिल्डिंग को कैसे हजरतगंज में खरीदा गया ऊ कहा जाता है कि इसमें संजय गुप्ता पूर्व आईएएस की भारी धनराशि काला धन लगा हुआ है।

राजकुमार गुप्ता उनकी पत्नी निर्मला गुप्ता व पुत्र विनोद गुप्ता व अन्य लोगों के खिलाफ आयकर महानिदेशक जांच को आय से अधिक संपत्ति की जांच करनी चाहिए की लखनऊ में बिहार व सिवान में वह छपरा में कैसे इतनी करोड़ों की अकूत संपदा का मालिक बन गया है यह तो सुनिश्चित है कि इसमें संजय गुप्ता पूर्व आईएएस का काफी काला धन लगा हुआ है उत्तर प्रदेश के जीएसटी के प्रवर्तन आयुक्त को राजकुमार गुप्ता केआरके कैटरर्स द्वारा की जा रही भारी कर की चोरी की जांच करनी चाहिए और इनके यहां कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारी गण बाराबंकी निवासी राम सेवक यादव कुक व सिद्धार्थ नगर निवासी अरुण गुप्ता कुक व सौरभ द्विवेदी कुक को समन जारी करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए जो गत कई वर्षों में हुई पार्टियों के आयोजनों की फेयर लिस्ट बता देंगे जिससे यह पता लग जाएगा कि इन्होंने विगत कई वर्षों में कितने लाखों रुपए की कितनी पार्टियों का आयोजन किया।

और कर की भारी चोरी की और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जिससे भारी कर की चोरी पकड़ी जाएगी।श्री संजय भाई जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश सामाजिक समरसता संगठन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सर्व श्री अनादि शुक्ला ने इस संवाददाता से अनौपचारिक भेंट वार्ता के दौरान कहा कि समाज में राजकुमार गुप्ता और भ्रष्टाचार के आरोपित संजय गुप्ता पूर्व आईएस गुजरात कैडर की संपत्तियां भारत सरकार को तत्काल जप्त कर लेनी चाहिए और सभी संबंधित विभागों को इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए चाहे वह आय से अधिक संपत्ति का आयकर का मामला हो या नगर निगम द्वारा कमर्शियल हाउस टैक्स का मामला हो या विद्युत कमर्शियल और घरेलू विद्युत चोरी का मामला हो या घरेलू सिलेंडरों के इस्तेमाल का मामला हो कमर्शियल के बजाय या संजय गुप्ता पूर्व आईएएस द्वारा राजकुमार गुप्ता व उनके परिवार के नाम से काले धन से खरीदी गई अकूत संपत्ति की प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गहनता से जांच करनी चाहिए तभी ऐसे भ्रष्टाचारी बेनकाब होंगे।

गरीबों के हित में छह सालों में जो कार्य हुए वे पहले कभी नहीं हुए: प्रधानमंत्री मोदी

भोपाल, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और वंचितों के हित में कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आज कहा कि देश में पिछले छह सालों के दौरान गरीबों के हित में जितने व्यवस्थित ढंग से कार्य हुए हैंए वे पहले कभी नहीं हुए। श्री मोदी ने सड़क किनारे ठेला लगाकर या फुटपाथ पर बैठकर कार्य करने वालों स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रारंभ की गयी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मध्यप्रदेश के एक लाख से अधिक हितग्राहियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं इस तरह से एक दूसरे को संबद्ध कर बनायी गयी हैं

जिससे गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों और आदिवासियों का व्यापक हित हो सके। इस दिशा में पिछले छह सालों में जिस तरह से व्यवस्थित ढंग से कार्य हुआ, वो पहले कभी नहीं हुआ। कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानए राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, अन्य मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी जुड़े। श्री मोदी ने इंदौर जिले के सांवेर निवासी झाड़ू बनाकर बेचने वाले दंपत्तिए ग्वालियर में चाट बेचने वाली महिला और उसके परिजनों तथा रायसेन जिले के सांची निवासी आर्गेनिक सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से संवाद भी किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया में जब भी महामारी या कोई अन्य संकट आता हैए उससे गरीब ही सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। देश में कोरोना संकट के दौरान भी यही हुआ। इसलिए केंद्र सरकार ने गरीबों के हित में कोरोना संकट की शुरूआत से कदम उठाए। केंद्र सरकार ने पिछले छह सालों के दौरान गरीबों के हित में जो योजनाएं बनायीं, वे सब एक दूसरे से संबद्ध हैं और इन सभी का कोरोना संकट के दौरान भी प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा इन्हीं योजनाओं से संबद्ध अन्य योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों के बारे में नयी योजना पर कार्य किया जा रहा है और अब देखा जाएगा कि उज्जवला, आयुष्मान और अन्य केंद्रीय योजनाओं का लाभ इन हितग्राहियों को मिल रहा है अथवा नहीं। यदि इन्हें अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो उन्हें इन योजनाओं का लाभ दिलाना भी सुनिश्चित कराया जाएगा।

मोदी ने कोरोना के बहाने असंगठित क्षेत्र को किया बर्बादः राहुल गांधी

नयी दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उन पर असंगठित क्षेत्र को खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि श्री मोदी ने पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब कोरोना महामारी के नाम पर इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। श्री गांधी ने बुधवार को यहां जारी एक वीडियो में कहा कि मोदी सरकार ने सुनियोजित तरीके से असंगठित क्षेत्र को तबाह करने का काम किया है। कोरोना को लेकर इस बार अचानक किया गया लॉकडाउन असंगठित वर्ग के लिए मृत्युदंड

जैसा साबित हुआ। श्री मोदी ने 21 दिन में कोरोना महामारी को ख़त्म करने का वादा किया था लेकिन ख़त्म किए करोड़ों रोज़गार और छोटे उद्योग। उन्होंने कहा कोरोना के नाम पर जो किया वो असंगठित क्षेत्र पर तीसरा आक्रमण है। गरीब तथा लघु एवं मध्यम श्रेणी के बिजनेस के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब आपने बिना कोई नोटिस लॉकडाउन किया ,आपने इनके ऊपर आक्रमण किया7 प्रधानमंत्री जी ने कहा 21 दिन की लड़ाई होगी, असंगठित क्षेत्र के रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। लॉकडाउन के खुलने के बाद का समय आया, आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा कि गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी।

नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए गए डोनाल्ड ट्रंप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साल 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उन्हें श्व- इजरायल के बीच शांति समझौता कराने के लिए नॉमिनेट किया गया। नॉर्वे संसद के क्रिश्चियन ताइब्रिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नामित किया। ताइब्रिंग नॉर्वे की संसद के चार बार से सदस्य हैं और नाटो की संसदीय असेंबली का हिस्सा हैं। उन्होंने यूएई और इजरायल के बीच बेहतर संबंधों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ट्रंप को श्रेय दिया। उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा, नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किए गए अन्य लोगों से यादा ट्रंप ने देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिशें की हैं। ट्रंप के लिए नॉमिनेशन पत्र में ताइब्रिंग ने लिखा, जैसी कि उम्मीद है कि अन्य मध्य पूर्वी देश संयुक्त अरब अमीरात के नक्शेकदम पर चलेंगे, यह समझौता एक गेम चेंजर हो सकता है।

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक

नयी दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र में मराठाओं को शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण देने संबंधी वर्ष 2018 के कानून को लागू करने पर रोक लगा दी लेकिन आदेश दिया कि जो इसका लाभ उठा चुके हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान न पहुंचाया जाए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम इस मामले की

सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। पीठ ने इस मसले के निस्तारण के लिए मामले को वृहद पीठ को सौंप दिया। पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश निर्धारित करेंगे कि यह मामले के निपटारे के लिए किस तरह की वृहद पीठ गठित की जाये और कौन उसकी अध्यक्षता करेगा। उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस वर्ष के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की प्रवेश संबंधी प्रक्रिया में कोई छेड़छाड़ न की जाए। उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को चुनौती देते हुए कई याचिकायें दायर की गयी थीं। पीठ ने कहा कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जायेगा जो वृहद पीठ को सौंपने के बारे में जरूरी आदेश पारित करेंगे। न्यायालय ने कहा कि अब नौकरियों और प्रवेश में मराठा आरक्षण का कोई प्रभाव नहीं होगा। इस वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में जो प्रवेश हो चुके हैं, उस पर हालांकि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ब्रिटेन में रुका, पर भारत में जारी है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल

पुणे, एजेंसी। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही एस्ट्राजेनेका कंपनी ने भले ही ब्रिटेन में ह्यूमन ट्रायल पर रोक लगा दी हो, लेकिन भारत में वैक्सीन का ट्रायल जारी है। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन में अपने अंतिम फेज के ट्रायल के दौरान मानव परीक्षण में शामिल एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने पर आगे के ट्रायल पर रोक लगा दी थी। भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल में किसी भी वॉलंटियर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरे फेज के ट्रायल में 100 से यादा वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई थी, लेकिन एक हफ्ता पूरा हो जाने के बाद भी इनपर कोई गलत रिएक्शन नहीं देखा गया। दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन बनाने वाले पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन को बनाने का जिम्मा लिया है।

कोरोनामुक्त होने वालों की संख्या नये शिखर पर

एक दिन में रिकॉर्ड 74,894 स्वस्थ

नयी दिल्ली, एजेंसी। देश में कोरोना संक्रमण के दिनोंदिन बढ़ते मामलों के साथ ही इस संक्रमण से मुक्ति पाने वालों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 74,894 लोगों के रोगमुक्त होने से लगातार दूसरे दिन स्वस्थ होने के मामले में नया रिकॉर्ड बना। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण से छुटकारा पाने वालों की संख्या 33,98,845 पर पहुंच गयी है।

वहीं कोरोना संक्रमण के 89,706 नये मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 43,70,129 हो गया। स्वस्थ होने वालों की तुलना में संक्रमण के नये मामले अधिक होने से सक्रिय मामले 13,697 बढ़कर 8,97,394 हो गये हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 1,115 संक्रमितों की मौत होने से मृतकों की संख्या 73,890 हो गयी। देश में सक्रिय मामले 20.53 प्रतिशत और रोगमुक्त होने वालों की दर 77.77 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.69 फीसदी है। कोविड-19 से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और यह 6,517 बढ़कर 2,43,809 हो गयी तथा 380 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 27,407 हो गया। इस दौरान 13,234 लोग संक्रमणमुक्त हुए जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 6,72,556 हो गयी। देश में सर्वाधिक सक्रिय मामले इसी राज्य में हैं। आंध्र प्रदेश में इस दौरान मरीजों की संख्या 1,163 कम होने से सक्रिय मामले 96,769 रह गये। राज्य में अब तक 4560 लोगों की मौत हुई है। वहीं कुल 4,15,765 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं। दक्षिणी राज्य कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान मरीजों की संख्या में 83 की कमी हुई है और राज्य में अब 96,937 सक्रिय मामले हैं। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 6,680 पर पहुंच गया है तथा अब तक 3,08,573 लोग स्वस्थ हुए हैं।

> स्वस्थ होने वालों की तुलना में संक्रमण के नये मामले अधिक होने से सक्रिय मामले 13,697 बढ़कर 8,97,394 हो गये हैं

कंगना के कार्यालय में अवैध निर्माण तोड़ने पर रोक

मुंबई, एजेंसी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित मणिकर्णिका फिल्म्स कार्यालय को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कथित तौर पर अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ दिया है। इस बीच बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कंगना रनौत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायालय की ओर से यह रोक गुरुवार दोपहर तीन बजे तक लगाई गई है हालांकि बीएमसी ने पहले ही अपनी कार्रवाई पूरी ली थी। न्यायालय इस मामले में गुरुवार को फिर सुनवाई करेगा। न्यायालय ने कंगना रनौत के कार्यालय में अवैध निर्माण को गिराने में इतनी जल्दबाजी करने के लिए बीएमसी से जवाब मांगा है। कल बीएमसी को इसका जवाब देना है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी देखते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गत 26 मार्च को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार बीएमसी और सभी संबंधित विभाग किसी के खिलाफ कोई विरोधात्मक कार्रवाई जल्दबाज़ी में ना करें। गौरतलब है कि कंगना एवं शिव सेना नेताओं के बीच जारी वाक् युद्ध के बीच बीएमसी ने यह कार्रवाई की है।

योगी ने लखनऊ, कानपुर तथा प्रयागराज में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में वृद्धि करने के दिए निर्देश

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद लखनऊ, कानपुर नगर तथा प्रयागराज में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में वृद्धि किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में इस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्यवाही सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से संचालित की जाए। मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने तथा कोविड-19 की बेहतर उपचार व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। इस उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार रणनीति बनाकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रति लोगों को सतत् जागरूक किया जाए। एल-2 तथा एल-3 कोविड चिकित्सालय में बेड्स की संख्या में वृद्धि की कार्यवाही लगातार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड-19 के दृष्टिगत प्रशिक्षण देकर कोविड अस्पतालों में मैनपावर बढ़ाने की कार्यवाही में तेजी लायी जाए। चिकित्सा कर्मियों को मेडिकल संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें पी0पी0ई0 किट, ग्लव्स, मास्क एवं सेनिटाइजर की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 से संक्रमित मरीजों से सी0एम0 हेल्पलाइन के माध्यम से भी संवाद स्थापित कर उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी प्राप्त की जाए।

उद्यमियों तथा निवेशकों के प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण पर बल देते हुए उन्होंने उद्योग बन्धु की बैठक को शीघ्र आहूत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे इस बैठक में उद्यमियों से संवाद स्थापित करते हुए उनका फीडबैक प्राप्त करेंगे। उन्होंने पशुओं के टीकाकरण के लिए अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश सी0 अवस्थी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

न्यू गणेश गंज व्यापार मण्डल ने बांटी आइवर मेकटिंग दवा

लखनऊ, संवाददाता। गणेश गंज मार्केट में बुधवार को कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए न्यू गणेश गंज व्यापार मण्डल ने आइवर मेकटिंग दवा का निःशुल्क वितरण किया। अध्यक्ष राजीव वोहरा ने बताया कि लखनऊ व्यापार मण्डल के सहयोग से कोरोना को हराने के लिए दवा का वितरण किया गया और कोविड-19 से बचने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। इस मौके पर न्यू गणेश गंज व्यापार मण्डल के कोषाध्यक्ष अमित अग्रहरि, महामंत्री मो0 अरशद, उपाध्यक्ष शकिम अंसारी, अजीम कुरेशी, विवेक गुप्ता, मंत्रीगण संजय चौरसिया, राजीव वैश्य, राम प्रसाद, संगठन मंत्री मो0 एहसान, मो0 साजिद तथा मीडिया प्रभारी गुंजन अरोड़ा मौजूद रहें।

अर्थव्यवस्था की तवाही और लोकतन्त्र पर मंडराते खतरों के विरूद्ध 14 सितंबर को देश भर में प्रदर्शन करेगी भाकपा

लखनऊ, संवाददाता। भारत की अर्थव्यवस्था को खंडहर में तब्दील कर देने और लोकतन्त्र को गहरे संकट में फंसा देने के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 14 सितंबर को सारे देश में प्रतिरोध दर्ज करायेगी। ज्ञातव्य हो कि इसी दिन संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। यह निर्णय गत दिन जूम 'एप' के माध्यम से संपन्न पार्टी के केन्द्रीय सचिव मण्डल की बैठक में लिया गया है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा करने वाली, गरीबी बढ़ाने वाली एवं जीवनयापन के साधनों को तहस नहस करने वाली मोदी सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों के विरूध्द जनता को संगठित किया जायेगा। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में लगातार झूठे दावे करने और झूठ बोलने वाली वित्त मंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, अतएव उनसे पद छोड़ने की मांग की जायेगी। भाकपा फजीवनयापन, समानता और न्याय के लिये- भारत और भारत के संविधान की रक्षा के लिये सदा प्रतिबध्द रही है और रहेगीफ, इस संकल्प के साथ आंदोलन किया जाएगा। भाकपा के उत्तर प्रदेश राज्य सचिव डा? गिरीश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधों की भरमार, भ्रष्टाचार और शासकीय गुंडागर्दी सहित उन सभी सवालों को उठाया जायेगा जिन्हें भाकपा विगत कई माहों से लगातार उठाती रही है।

बेरोजगार युवाओं के समर्थन में आए अखिलेश, 9 बजे, 9 मिनट पर बत्तियां बुझाने का किया आह्वान

लखनऊ, संवाददाता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए लोगों से बुधवार रात नौ बजे, नौ मिनट तक बत्तियां बुझाने की अपील की। यादव ने ट्वीट किया, 'मुट्ठियां जब बंध जाती हैं नौजवानों की, नींद उड़ जाती है जुल्मी हुक्मरानों की। आइए युवाओं व उनके परिवार की बेरोजगारी-बेकारी के इस अंधेरे में हम आज रात 9 बजे, 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझाकर क्रांति की मशाल जलाएं, उनकी आवाज में आवाज मिलाएं! नो मोर बीजेपी। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं के पास डिग्री और योग्यता है, इसके बावजूद वह बेरोजगार हैं और सरकार उनके लिये कुछ भी नहीं कर रही है।

संसाधन के अभाव में एसपीसी का काम छोड़ा

लखनऊ, संवाददाता। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने कार्मिकों तथा अन्य संसाधन की कमी के कारण स्टूडेंट पुलिस कैडेट (एसपीसी) प्रोग्राम का काम छोड़ दिया।पूर्व डीजीपी ओ पी सिंह ने आईजी नागरिक सुरक्षा अमिताभ ठाकुर को मई 2018 में अपने स्तर से एसपीसी का राज्य नोडल अधिकारी बनाया था. तब से वे लगातार एसपीसी का काम देख रहे थे. इस दौरान अमिताभ ने कई बार डीजीपी तथा गृह विभाग को कार्मिकों तथा अन्य संसाधनों की भारी कमी के बारे में लिखा किन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. अंत में अमिताभ ने डीजीपी को स्पष्ट कर दिया कि वे संसाधनों के अभाव में यह काम नहीं देख सकते हैं और इसे किसी अन्य को दे दिया जाये। डीजीपी एच सी अवस्थी ने एसपीसी का काम प्रशिक्षण मुख्यालय को देने के आदेश किये हैं।

मायावती शासन की अनियमितताओं पर शुरू होगी कार्रवाई

लखनऊ, संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के लिए अब मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। योगी सरकार ने नियंत्रक और महालेखाकार (कैग) की रिपोर्ट के आधार पर उन पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस रिपोर्ट ने 2007 से 2012 के बीच मायावती के नेतृत्व वाली सरकार के शासन की विसंगतियों का खुलासा किया है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन मायावती सरकार ने गाजियाबाद में कृषि भूमि को आवास भूमि में बदला और इसके लिए प्रॉपर्टी डेवलेपर्स से अपेक्षित रूपांतरण शुल्क नहीं लिया। मायावती सरकार के फैसले से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) को 572.48 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ और दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन करते हुए चुनिंदा प्रॉपर्टी डेवलपर्स को ही यह लाभ दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि जीडीए ने दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में हाई-टेक टाउनशिप के रूप में चिन्हित 3,702.97 एकड़ सहित कुल 4,772.19 एकड़ क्षेत्र के लिए प्रॉपर्टी डेवलपर्स के लेआउट प्लान्स को मंजूरी दी थी।

मानदंडों के खिलाफ जाकर कृषि भूमि को उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया, क्योंकि इसका भूमि उपयोग बदलकर आवासीय कर दिया गया था और इसके लिए कोई रूपांतरण शुल्क नहीं लिया गया था। इस फर्म में उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स और सन सिटी हाई-टेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड जैसे दो डेवलपर्स शामिल हैं। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 अप्रैल, 2010 को एक आदेश जारी किया था इसके बाद यह वित्तीय अनियमितताएं हुई।

मुनव्वर राना की बेटी ने पुलिस पर लगाया नजरबंद करने का आरोप, कहा

मेरे अधिकारों का हो रहा हनन

लखनऊ, संवाददाता। मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुमैया राना ने उन्हें नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने सुमैया को नजरबंद किए जाने के आरोपों को गलत करार दिया है। सुमैया की अगुवाई में प्रदेश में कोविड-19 महामारी से निपटने के सरकारी प्रबंधों की नाकामी के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित कालिदास मार्ग चौराहे पर प्रदर्शन होना था। सुमैया ने बुधवार को बताया कि कैसरबाग स्थित उनके घर के बाहर सोमवार रात से पुलिस का कड़ा पहरा बैठाकर उन्हें घर में नजरबंद कर रखा गया है। धरना प्रदर्शन की योजना अपनी जगह है लेकिन उनकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी भी है। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। यह उनके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को लाल कुआं क्षेत्र स्थित उनके पिता मुनव्वर राना के घर के बाहर भी पुलिस तैनात की गई थी। सुमैया ने बताया कि पुलिस ने उन्हें नजरबंदी के सिलसिले में कोई आदेश या नोटिस नहीं दिखाया है। हालांकि मंगलवार को उन्हें पुलिस का एक नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई गई है। सुमैया ने बताया कि नोटिस में यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में हजरतगंज तथा गौतम पल्ली इलाके में धरना प्रदर्शन को प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी अगुवाई में मंगलवार को प्रदेश में कोविड-19 महामारी से निपटने के सरकारी प्रबंधों की नाकामी के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित कालिदास मार्ग चौराहे पर प्रदर्शन होना था।

भ्रष्टाचार पर योगी का हंटर, महोबा एसपी मणि लाल पाटीदार सस्पेंड

लखनऊ, संवाददाता। भ्रष्टाचार के खिलाफजीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए महोबा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मणि लाल पाटीदार को निलंबित कर दिया है। सीएम योगी ने लगातार दूसरे दिन राज्य के बड़े पुलिस अधिकारी के खिलाफबड़ी कार्रवाई की है। मणि लाल पाटीदार पर परिवहन में लगी गाड़ियों के चलाए जाने हेतु अवैध रूप से पैसे मांगने और वाहन स्वामी के उत्पीड़न का आरोप लगा है। महोबा में मणि लाल पाटीदार के स्थान पर अरुण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश गृह विभाग के प्रवक्ता के अनुसार महोबा के पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन पर गिट्टी के परिवहन के लिए लगी गाड़ियों के चलाए जाने के लिए अवैध रूप से धन की मांग की गई थी, जिसे पूरा नहीं किए जाने पर वाहन स्वामी का पुलिस के माध्यम से उत्पीड़न किया गया। आईपीएस अधिकारी पाटीदार को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और उनके साथ पर लखनऊ कमिश्नरेट के पुलिस उपायुक्त अरुण कुमार श्रीवास्तव को महोबा का नया एसपी बनाया गया है। बता दें कि चौबीस घंटे पहले ही अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में ढिलाई बरतने और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया। उन्हें भी पुलिस महानिदेशक कार्यालय से संबद्ध किया गया है। अभिषेक दीक्षित पर एसएसपी प्रयागराज के रूप में तैनाती की अवधि में गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर अनियमितताएं करने तथा शासन व पुलिस मुख्यालय के निर्देशों का पालन सही ढंग से नहीं करने का आरोप है। पोस्टिंग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप भी उन पर लगे हैं। प्रयागराज में बीते तीन महीनों के दौरान लंबित विवेचनाओं में भी लगातार वृद्धि हुई।

योग से हराया कोविड

लखनऊ, संवाददाता। इंटर फेथ मानवता अलायंस केफकोविड बचाओ के नियमों के प्रचार एवं भेदभाव दूर करने में धर्म गुरुओं की भूमिकाफ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर एक धर्मगुरु शिरकत करते ब्रम्हाकुमारी राधा बहन ने कहा कि इस महामारी के समय में सबसे प्रमुख बात है अपने मन की शक्ति को, ऊर्जा के स्तर को ऊंचा बनाए रखना, सोच को सकारात्मक बनाना, किसी भी भय- चिंता से मुक्त रहना, अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि संपर्क द्वारा ज्ञात होने पर प्रभावित रोगियों को उन्होंने स्वयं काढ़ा बनाकर पिलवाया तथासेंटर पर ब्रम्हाकुमारी बहनों ने संगठित योगाभ्यास (मेडिटेशन) करके शक्ति के वाइब्रेशन रोगी के प्रति भेजें जिसमें बड़ी सफलता मिली. यहां तक कि वेंटिलेटर की स्थिति तक पहुंचा रोगी भी स्वस्थ हो गया, अपने सारगर्भित संक्षिप्त उद्बोधन के अंत में उन्होंने योग का अभ्यास करा बताया कि कैसे हम परमात्मा से संबंध जोड़, परमात्म शक्ति प्राप्त कर, अपने चारों ओर सुरक्षा कवच बना सदा सुरक्षित रह सकते हैं।

महंगी बिजली खरीदकर टोरेंट पावर को सस्ते में बेच रहा दक्षिणांचल निगम

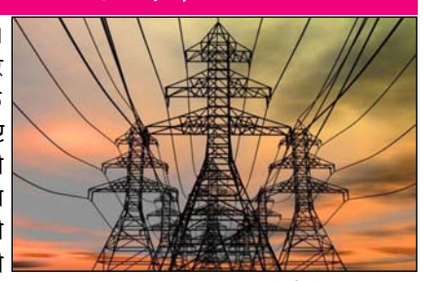

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के प्रस्तावित टैरिफ से स्पष्ट हो गया है कि सरकारी विद्युत वितरण निगम महंगी दरों पर बिजली खरीद कर निजी क्षेत्र की कंपनियों को सस्ती दरों पर बेच रही है। ऑडिट में भी माना गया है कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम 5.26 रुपयेध्यूनिट की दर पर खरीद कर टोरेंट पावर आगरा को 4.45 रुपयेध्यूनिट की दर पर बेच रहा है। इससे निगम को हर साल 162 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इसका खामियाजा प्रदेश की तीन करोड़ उपभोक्ताओं को महंगी बिजली के रूप में भुगतना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति व्यवस्था के निजीकरण की चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के प्रस्तावित बिजली दरों के आंकड़ों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला है कि निजीकरण की व्यवस्था सफल नहीं होगी। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया की दक्षिणांचल कंपनी द्वारा स्वतंत्र ऑडिटर फर्म से कराई गई ऑडिट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वर्मा ने सरकार से टोरेंट पावर के अनुबंध की समीक्षा करने के साथ ही मामले की जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने निजीकरण के दोनों प्रयोगों टोरेंट पावर व नोएडा पावर की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी, लेकिन जांच अब तक लंबित है। उन्होंने सरकार से दोनों निजी घरानों के अनुबंध को समाप्त कर जनहित में निजीकरण पर प्रदेश में रोक लगाने की भी मांग की है।

अपने ही कोरोना योद्धा के लिये कोविड अस्पताल में नहीं है सुविधायें

कोविड एल-2 अस्पताल की बदहाल हालत-चादर तक नहीं है उपलब्ध

लखनऊ, संवाददाता। जिला प्रशासन लाख दावे कर ले परन्तु कोविड अस्पतालों की जो हालत है वह केवल भुक्तभोगी ही बता सकता है। स्वास्थ्य विभाग जब अपने ही डाक्टर और फार्मासिस्ट को सुविधायें नही दे पा रहा है तो बाकी साधारण मरीजों के बारे में तो कल्पना ही की जा सकती है। कोविड प्रोटोकाल के अनुसार मरीज की पहचान को गोपनीय रखा जाता है। इसलिये केवल इतना कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग का एक फार्मासिस्ट अपनी कोविड ड्यूटी करते हुये कोरोना पाजिटिव हो गया। डायबिटीज का मरीज होने के कारण और सांस लेने में दिक्कत होने के कारण उसे कोविड एल-2 अस्पताल में भर्ती किया गया। जहां सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहां तक बेड पर चादर तक नहीं दी गयी। बाकी का तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। जिला प्रशासन प्रतिदिन दावे करता है कि फलां अस्पताल में एल-1 के, एल-2 के और एल-3 अस्पतालों में इतने बेड खाली पड़े है। भुक्तभोगियों के अनुसार जब इतने बेड खाली है तो होम आइसोलेशन क्यों किया जाता है? लोग एक या दो कमरे के मकानों में रहते है वहां होम आइसोलेशन के चक्कर में पूरा घर पाजिटिव हो जाता है। यहां तक लोगों को आक्सीजन सिलिण्डर, के साथ पल्स आक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीदने की फ्री सलाह दे दी जाती है। डाक्टरों के अनुसार जब मरीज केवल पाजिटिव होता है और उसे कोई दिक्कत नहीं होती है तो उसे केवल आइसोलेशन के लिये कोविड एल-1 अस्पताल में आइसोलेट किया जाता है। जब मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे एल-2 में एडमिट किया जाता है। यहां आक्सीजन की सुविधा होती है। यदि इससे ज्यादा हालत खराब होती है और वेन्टीलेटर की आवश्यकता होती है तो उसे एल-3 अस्पताल जैसे केजीएमयू या पीजीआई में एडमिट कराया जाता है। एल-3 अस्पतालों मे बेड खाली होते ही नहीं है कई-कई दिनों के बाद नंबर आता है। मजबूरी में पीड़ित निजी अस्पतालों में खुद को लुटाने जाता है। यहां भी सरकार और जिला प्रशासन दावे लाख कर ले परन्तु निजी अस्पतालों की लूट-खसोट में कोई कमी नहीं आती है।

मंत्री द्वारा सेक्स स्कैंडल बचाव के 20 लाख एफआईआर की मांग

लखनऊ, संवाददाता। एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने सीएमओ ऑफिस ललितपुर में ड्राईवर पद पर नियुक्त राजकुमार दुबे द्वारा 06 सितम्बर 2020 की रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या के बाद उनके एक वायरल विडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज किये जाने की मांग की है। अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी तथा अन्य अफसरों को भेजी अपनी शिकायत में नूतन ने कहा कि राजकुमार दुबे ने आत्महत्या के पूर्व एक विडियो बनाया जिसमे उन्होंने कई लोगों पर उन्हें फर्जी सेक्स स्कैंडल में फंसाने तथा ललितपुर निवासी मंत्री मन्नू कोरी द्वारा उनसे इससे बचाने के लिए 20 लाख रूपये लेने के बाद भी नहीं बचाने जैसे गंभीर आरोप लगाये। नूतन के अनुसार राजकुमार दूबे का यह विडियो सामने आने के बाद डीएम ललितपुर ने इस संबंध में मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए हैं किन्तु यह पर्याप्त नहीं है।

भाजपा चुन-चुनकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही

लखनऊ, संवाददाता। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि भाजपा सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की मुहिम चलाकर संविधान की अवमानना कर रही है। जो भी सरकार के साथ अपनी असहमति दिखाता है, भाजपा सरकार उसके पीछे पड़ जाती है। भाजपा सरकार चुन-चुनकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है। अपर निजी सचिव अमर सिंह पटेल पर फर्जी आरोप लगाकर बर्खास्तगी की कार्रवाई द्वेषपूर्ण है। इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर तो आज तमाम मंत्री, अधिकारी भी अपनी बात रखते हैं। सरकार कोई छुईमुई नहीं है कि उसके किसी काम की तनिक आलोचना भी उसे इस कदर नागवार गुजरे कि किसी लोक सेवक की जिंदगी ही बर्बाद कर दी जाए, यह कहां का न्याय है। भाजपा सरकार अपने अहंकार में उचित-अनुचित, सही-गलत का भेद भूल गई है। वह तो बस सर्वत्र अपना एकाधिकार करने और दिखाने की साजिशें रच रही है। समय आने पर मिलेगा वोट लेकर जनता को धोखा देने वाली भाजपा को जवाब।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की 21 सितंबर से प्रस्तावित आंदोलन की ऑनलाइन समीक्षा

लखनऊ, संवाददाता। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों से ऑनलाइन वार्ता कर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा 21 सितंबर से प्रस्तावित जागरूकता आंदोलन के आगाज पर जनपदों में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि जनपदों में कर्मचारी कोरोना से लड़ने के साथ-साथ अपनी समस्याओं के लिए भी जागरूक है। 21 सितंबर से मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव कार्मिक को प्रत्येक जनपद से जनपद शाखा एवं जनपद में कार्यरत संगठनों के माध्यम से पत्र लिखकर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि कोविड-19 के दौरान कर्मचारियों के सामने कई नई समस्याएं आ रही हैं, जिनसे मुख्य सचिव को अवगत कराया जाएगा। कोविड की ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारी महीनों से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन उनको कोई अवकाश नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण दर्जनों कर्मचारी बीमार हो गए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि कोरोना नियंत्रण में लगे हुए कर्मचारियों को सप्ताह में 1 दिन का अवकाश जरूर प्रदान किया जाए ताकि सप्ताह भर की संवेदनशील ड्यूटी से 1 दिन के अवकाश में तरोताजा होकर कर्मचारी पुनः अपनी ड्यूटी जोश और उल्लास के साथ कर सकें। जे एन तिवारी ने मुख्य सचिव को अवगत कराया है कि आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाए जाने, कार्यालयों में हेल्प डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने ,रिक्त पदों को भरे जाने, कर्मचारियों का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं किए जाने ,कर्मचारियों की समस्याओं के लिए अलग पोर्टल विकसित किए जाने, परिवहन, वन एवं लोक निर्माण विभाग में 2001 तक कार्यरत दैनिक कर्मियों को रेगुलर किए जाने की मांग पर सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है। उन्होंने मुख्य सचिव से मांग किया है कि कोविड अनलॉक 4 में अब प्रदेश में लगभग सामान्य काम काज हो रहे हैं, ऐसे में कर्मचारियों की समस्याओं के लिए मुख्य सचिव स्तर पर संवाद हीनता बने रहने से कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न हो रहा है एवं कर्मचारियों की समस्याएं लंबित होती जा रही हैं। जे एन तिवारी ने मुख्य सचिव को अवगत कराया है कि कर्मचारी कोरोना संकटकाल में पूरी तरह से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन कर्मचारियों की समस्याओं का उच्च स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।

उन्होंने आगाह किया है कि यदि संगठन एवं शासन के बीच संवाद हीनता बनी रही तो कर्मचारियों का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। आज की ऑनलाइन चर्चा में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी के अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसवंत सिंह, मंत्री निरंजन श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, महेंद्र पांडे, श्रीमती अजय लक्ष्मी ,रमेश चंद्र खरे, हरगोविंद यादव ,रिंकू राय, नारायण जी दुबे, विनय द्विवेदी, रजनीश श्रीवास्तव ,रमेश राय, राजेश श्रीवास्तव , घनश्याम मिश्रा, आशीष त्रिपाठी ,बृजभूषण मिश्रा सहित दर्जनों पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए।

सामाजिक संगठन जल्द बेरोज़गार लोगों के लिए थाली-ताली का मार्च करके

लखनऊ, संवाददाता। आज जारी अपने बयान में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संयोजक मुहम्मद आफाक ने आज लॉकडाउन हटाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना जैसी बीमारी डब्लू.एच.ओ. से मोटी रकम लेने का बेहतरीन रास्ता आसान किया और जनता को भ्रामित करके घरों में नज़रबंद करके उनके घरों से मेहनत-मजदूरी की कमाई खर्चा करवायी और जनता को कंगाली की कगार पर छोड़ दिया। थाली-ताली वाली यह सरकार पूरी तरह फेल हो गयी। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की कीमत लगभग 90 रूपया प्रति लीटर आदि चीजों की महंगाई से जनता जूझ रही है और बेखबर सरकारें आर0एस0एस0 के एजेंडे को और सावारकर व गोलवलकर के सपनों को साकार करने में लगी है। यह बात भी जनता की समझ में आ गयी है कि यह सरकार मनुवादियों की सरकार है।

चिनहट में चल रही थी नकली देसी शराब की फैक्ट्री, दो गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से 75 लाख की नकली शराब व तमाम सामान बरामद किया

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी के चिनहट थाना क्षेत्र में नकली देसी शराब की फैक्ट्री चल रही थी। बुधवार को लखनऊ पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारकर 75 लाख रुपये की देसी शराब, खाली शीशियां, ढक्कन और अन्य सामान बरामद किया। पुलिस ने मौके से दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी देते हुए डीसीपी पूर्वी, लखनऊ चारु निगम ने बताया कि फैक्ट्री से निर्मित नकली शराब की आपूर्ति लखनऊ सहित आस-पास के जनपदों में होती थी। इनमें बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच और पीलीभीत जैसे जिले शामिल हैं। पुलिस ने मौके से सौरभ मिश्रा और अनुज जयसवाल को गिरफ्तार किया है। शराब ठेकेदार आदित्य कुमार समेत गुलशन उर्फ गुल्लू, अभिषेक सिंह उर्फ रिशु सिंह, परेस, विकास, आशुतोष, बबलू, अंकित और अमित फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। चिनहट पुलिस ने शराब गिरोह के बड़े गैंग का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। डीसीपी ने बताया कि नकली शराब की फैक्ट्री चिनहट थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में स्थित एक मकान में चल रही थी। पुलिस ने मौके से 12 ड्रम अपमिश्रित अल्कोहल, 9 जेरिकेन अपमिश्रित अल्कोहॉल, 6 पिपिया अपमिश्रित अल्कोहॉल, 304 पेटी पावरहाउस कंपनी की बोतलें, बार कोड स्टीकर, बोतल सील करने की मशीन समेत अन्य उपकरण बरामद किए हैं।डीसीपी चारू निगम ने कहा कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट नकली शराब कारोबार की रिपोर्ट शासन को भेजेगा। राजधानी में पिछले काफी समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। आबकारी विभाग की अनदेखी और लापरवाही के चलते लखनऊ सहित कई जनपदों में यह कारोबार फैला हुआ था। लखनऊ पुलिस अपनी रिपोर्ट आबकारी विभाग के खिलाफ भेजेगा। ताकि आबकारी विभाग के दोषी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके।

बुंदेलखंड के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष,आत्महत्या किये किसानों के परिजनों से की मुलाकात

झांसी/लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू बुंदेलखंड के दौरे पर हैं, पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान की बैठकों में शामिल हुए, साथ ही साथ बुंदेलखंड के झांसी जिले पहुंचे अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू ने आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर रहे किसानों और मजदूरों के परिजनों से मिले। प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पूरे बुंदेलखंड को सरकार ने किसानों की कब्रगाह में तब्दील कर दिया है। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते किसान आत्महत्या को मजबूर है। गरीब विरोधी नीतियों के कारण मजदूर आत्महत्या करने को विवश हैं। युवा विरोधी नीतियों के चलते बेरोजगारी की मार खाए नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। झांसी दौरे पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने जारी बयान में कहा कि बुंदेलखंड में बेमौसम बारिश से मूंग, उड़द, मूंगफली की फसलें बर्बाद हो गई। किसानों को एक पाई की भी मुआवजा राशि मयस्सर नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीड़ित किसानों ने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत किसानों को एक पैसा की बीमा राशि का भुगतान नहीं हुआ है। गलत नीतियों के कारण अन्ना जानवरों का प्रकोप बहुत तेजी से फैला है। किसान दिन-रात, दोपहरी, चैकीदारी करने को मजबूर है। श्री अजय कुमार लल्लू ने बताया कि कई पीड़ित किसानों ने उन्हें बताया कि बुंदेलखंड में निजी नलकूप लगाने पर सरकार द्वारा 63 हजार रुपए अनुदान देने का प्रावधान था। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी एक भी किसान को फूटी कौड़ी नहीं मिली है। उन्होंने

दर्जनों गांवों का भ्रमण किया। श्री अजय कुमार लल्लू ने पहला उदाहरण देते हुए कहा कि बीते दिनों चिरगांव ब्लॉक के बेरबई ग्राम के किसान प्रेम नारायण रैकवार ने कर्ज के कारण मौत को गले लगा लिया। पीड़ित परिजनों का कहना कि प्रेमनारायण लाकडाउन में फरीदाबाद से पैदल गांव आये थे। उनके चार भाई हैं, पूरा परिवार मजदूरी पर आश्रित है। डेढ़ बीघा खेती है, उड़द की खेती थी। सूखे -ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने अपनी बेटी की शादी किया था, 2 लाख साहूकार से कर्ज लिया व 50 हजार बैंक से कर्ज लिया है। साहूकार व बैंक से कर्ज चुकाने का चैतरफा दबाव था, पीड़ित ने तहसील से लेकर जिलाधिकारी से भी गुहार लगाई लेकिन किसी ने सुधि नहीं ली मजबूरन रैकवार ने मौत को चुना। परिजनों का यह भी कहना है कि सरकार की तरफ से अब तक न कोई मुआवजा मिला और न ही किसी तरह की और आर्थिक मदद मिली। उन्होंने दूसरी दुःखद आत्महत्या का जिक्र करते हुए बताया कि जनपद झांसी के गुरसराय ब्लॉक के ग्राम शहपुरा खुर्द के किसान स्व. लोकेंद्र सिंह कर्ज के बोझ व सरकारी मशीनरी के दबाव के कारण बेबस हो गए थे। परिजनों का कहना है कि उनके ट्रैक्टर से एक दुर्घटना हुई थी जिसके एवज में कोर्ट ने 5 लाख दंड दिया। खेत बेचकर आधा रुपया चुकता किया था। बैंक में 50 हजार का कर्ज था, फसल बर्बाद हो चली थी। सरकारी बाबू हर रोज तंग करता था, मानसिक दबाव में थे। अंत में उन्होंने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू ने जारी बयान में बताया कि जनपद झांसी के मऊरानी तहसील के छोटी सुजारी ग्राम सभा के राघवेंद्र सिंह लोधी ने फसल बर्बादी, साहूकारों के कर्ज व आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर जीवन लीला समाप्त कर ली। वे तीन भाई थे, छह बच्चों के पिता के साथ वे कुल तीन भाई थे, दो बीघे की खेती थी। परिजनों का कहना है कि उनके मरने के बाद सरकारी अमला आया तो, लेकिन किसी तरह की कोई मदद न उस वक्त मिली न अब तक सरकार की तरफ से कुछ मिला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह है भाजपा सरकार की हकीकत। देश का अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है और प्रधानमंत्री मोर के साथ वीडियो शूट करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी टीम 11 की फर्जी बैठकों से फुर्सत तक नहीं है। दौरे पर साथ रहे श्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में पूरे बुंदेलखंड के लिए श्री राहुल गांधी जी की पहल पर बुंदेलखंड पैकेज दिया गया।

आवारा कुत्ते से बाइक सवार टकराया, गंभीर घायल

जहानाबाद, फतेहपुर । जनपद प्रयागराज से हमीरपुर की तरफ जा रहे एक बाइक में दो सवार युवक विमल पुत्र विशंभर व राजेश पुत्र हरिश्चंद्र जैसे ही कस्बा के मोहल्ला पोजेपुर के निकट पहुंचे तभी अचानक रोड पर कुत्ता आ गया जिससे बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों बाइक सवार युवक रोड पर गिर गए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए द्य राहगीरों ने उन्हें पास के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जा रहा है द्य घायल विमल ने बताया की प्रयागराज से हमीरपुर जा रहा था द्य जैसे ही जहानाबाद कस्बे में आया तो आवारा कुत्ता के आने से बाइक अनियंत्रित हो गई जिससे दोनों लोग घायल हो गए।

तहसीलदार ने किया सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का निरीक्षण

जहानाबाद, फतेहपुर । मंगलवार को कस्बा में तहसीलदार गणेश सिंह और क्षेत्रीय लेखपाल बृजेंद्र प्रताप सिंह ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में पहुंच कर निरीक्षण किया।

निरीक्षण दौरान क्षेत्रीय लेखपाल बृजेश सिंह ने बताया कि आज जिला अधिकारी के निर्देशानुसार नवीन मंडी समिति कोड़ा जहानाबाद में पहुंच बिंदकी तहसीलदार ने निरीक्षण करने के दौरान गेहूं के अलग-अलग 2 सैंपल और एक चावल का सैंपल भरा। उसके बाद कस्बे की दुकानों में शैलेंद्र सिंह , शिव सागर, संतोष कुमार तथा ज्योति अवस्थी की दुकानों में पहुंच गेहूं और चावल के सैंपल भरे। इसके साथ-साथ गरीबों का आने वाला अनाज संतोषजनक वितरण करते हुए पाया गया। लालू गंज तिराहे समीप रामा देवी की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान वितरण दिवस में बंद पाई गई जिसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

अमौली कस्बा की गलियों में भरा है गंदगी का अंबार

जिम्मेदार कर रहे हैं अनदेखी

जहानाबाद, फतेहपुर । अमौली कस्बा के कई प्रमुख गलियों पर वर्तमान समय स्वच्छ भारत मिशन की जुम्मेवारो द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं द्य जहां गलियो व नालियों में भरा हुआ है कचरा। जहां सफाई कर्मी भी नहीं पहुंच कर अपनी जिम्मेवारी से सफाई करने का कार्य कर रहे हैं और क्षेत्रीय अमोली प्रधान एवं ग्राम विकास सचिव के साथ-साथ एडीओ पंचायत क्षेत्र में फैली गंदगी से संबंधित कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिस कारण अमौली की गलियों में गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है जिससे साफ जाहिर होता है कि कि वर्तमान सरकार के मूल प्लान स्वच्छ भारत

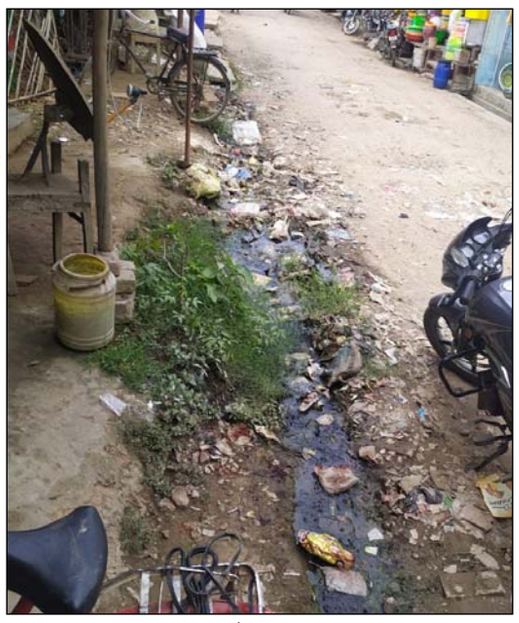

मिशन कि ऐसे ही गैर जिम्मेवार लोगों द्वारा स्वच्छता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं द्य जहां नागरिकों को गंदगी के बीच सांस लेना मजबूरी बनती जा रही है।

सूत्रों की माने तो क्षेत्रीय लोगों का कथन है कि ग्राम प्रधान शिवकुमारी पत्नी बद्दू सोनकर विकास के साथ-साथ कस्बे के गलियों में साफ-सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं जिससे अमोली के मूल निवासियों को कई बीमारियों से ग्रसित होने की अग्रिम आशा जताई जा रही है।

बिजली कटौती से ग्रामीणों के रातों की नींद भी हराम

क्षेत्र की जनता कर रही है पावर हाउस घेराव की तैयारी बन रही है रणनीति

हुसैनगंज, फतेहपुर । भिटौरा ब्लाक क्षेत्र के हुसैनगंज कस्बे के समीप स्थित कैथपुरवा पावर हाउस से क्षेत्र के लोगों को मिलने वाली बिजली की हालत दयनीय हो गई है। जरूरत के समय किसानों व क्षेत्र की जनता को विद्युत आपूर्ति सही ढंग से नहीं मिल पा रही है, इस समय हालत यह है कि हुसैनगंज इलाके के करीब 310 गांव के लोगों को बमुश्किल 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिससे किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, वहीं क्षेत्र की जनता की रातों की नींद हराम हो गई है बिजली की समस्या से परेशान क्षेत्र के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि तक बिजली की समस्या को लेकर मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा बिजली समस्या का हल नहीं निकल पाया है, फतेहपुर के राधा नगर से हुसैनगंज पावर हाउस तक आई 33 हजार केवीए की लाइन इतनी जर्जर हो चुकी है कि लोड अधिक पढ़ने के कारण आए दिन टूट कर गिरते रहते हैं जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है।लेकिन अभी तक तारों को बदला नहीं जा सका है, हुसैनगंज क्षेत्र को जो थोड़ी बहुत बिजली आपूर्ति होती भी है तो लाइन मैन सही तरीके से बिजली आपूर्ति को चलनें नहीं देते,पैसों के लालच में बीच-बीच में लाइन सही करने के लिए सिट डाउन भी ले लेते हैं जिससे बिजली सही तरीके से नहीं मिल पाती है, बिजली की समस्या से परेशान होकर क्षेत्र की जनता अब ऊब चुकी है।प्रदेश सरकार का ग्रामीण इलाके को 18 घंटे बिजली आपूर्ति करने का दावा पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्षेत्र की जनता और किसान बिजली की समस्या से परेशान हैं। किसानों की खेती बिजली न मिल पाने के कारण सूखने की कगार पर है, बिजली की समस्या से आजिज आकर क्षेत्र की जनता ने अब पावर हाउस का घेराव करनें का मन बना चुकी है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

बिजली विभाग के एसडीओ फूलचंद भारतीय का कहना है कि बिजली आपूर्ति की जाती है, लेकिन पावर हाउस से पांच फीडरों को एक साथ बिजली की आपूर्ति नहीं की जा सकती, अगर सभी फीडरों की आपूर्ति चालू कर दी जाती है तो 33 हजार केवीए की लाइन टूट जाती है ,इसलिए सभी फीडरों को एक साथ बिजली की आपूर्ति नहीं की जा सकती, बेरागढीवा स्तिथ पावर हाउस का कार्य चल रहा है बन जाने के बाद बिजली की समस्या दूर हो पाएगी!

क्षेत्र में बढ़ता जा रहा मक्छरजनित बीमारी का प्रकोप

- प्रधानों की बेरुखी व ग्रामीणों की लापरवाही से बढ़ता जा रहा संक्रामक बीमारी का दायरा

जहानाबाद, फतेहपुर । अमौली विकासखंड के ग्राम नसेनिया में इन दिनों बीमारी का प्रकोप आए दिन बढ़ रहा है जिससे नागरिकों में बीमारी के चलते भय व्याप्त है।

जानकारी के अनुसार विकासखंड अमौली के गांव नसेनिया में स्वास्थ्य विभाग शासनादेश अनुसार कैंप लगाकर मरीजों का उपचार जारी किया था। वही साफ सफाई से संबंधित ग्राम प्रधान को अवगत कराया था। जहां ग्रामीणों की लापरवाही व ग्राम प्रधान की अनदेखी से गांव क्षेत्र में गंदगी का प्रकोप होने से डेंगू मच्छर पनपने के आसार हैं। बताया जाता है कि उक्त गांव के ही पुनीत उर्फ शिवम त्रिवेदी पुत्र सुरेश उर्फ नन्हे उम्र 16 वर्ष आज मंगलवार को शाम 4:30 बजे डेंगू से बीमार युवक की उपचार दौरान मौत हो गई जिससे परिजनों में कोहराम मच गया।

बताया जाता है कि मृतक के अन्य दो भाई भी अस्पताल में भर्ती होकर उपचार करा रहे हैं।

वर्तमान समय विकासखंड देवमई और अमौली के कुछ ग्राम पंचायतों में इन दिनों गांव में गंदगी एकत्रित होने से डेंगू मच्छर पनपने से बीमारी फैलने के आसार है। जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम में बीच-बीच में कैंप लगाकर कुछ ग्रामों में उपचार भी कर रही हैं । वही ग्रामीणों का कथन है कि जनपद के जिलाधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी के दिशा निर्देशन पर कुछ ग्राम पंचायतों में बीमार लोगों के उपचार हेतु लगातार कैंप लगाकर स्वस्थ होने तक कैंप लगाने हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक -दो कैंप लगाकर अपनी मौजूदगी दर्शाने का कार्य कर रहे हैं और बीमारी बढ़ती जा रही है द्य गरीब लाचार लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में उपचार कराने में असमर्थ हैं द्य वही कुछ ग्रामीण लोग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होकर अपना उपचार भी करा रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हाल में घोषित कमेटियों से सदस्यों के साथ करेंगी बैठक

वीडियो कान्फ्रेंसिंग से करेंगी संवाद, हर कमेटी का निर्धारित होगा टास्क

बैठक में तय होगी हर सदस्य की जिम्मेदारी और जबाबदेही

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जल्द ही हाल-फिलहाल में घोषित कमेटियों के सदस्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक करेंगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों यूपी कांग्रेस के लिए सात नई कमेटियों का गठन किया गया है7 एक तरफ कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ सात कमेटियों के जरिये एक मजबूत व्यूह रचना की गई है जिसको आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी तैयारी के बतौर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गाँधी ने कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, पंचायतों के चुनाव के लिए पंचायती राज चुनाव तैयारी समिति, प्रचार-प्रसार कमेटी, प्रशिक्षण एवं कैडर निर्माण समिति, मेनिफेस्टो निर्माण समिति, सदस्यता अभियान समिति और संपर्क एवं ज्वाइनिंग समिति बनाई है।

इसके साथ ही साथ वह उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार के बाद सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें निर्देश देंगी और आगामी संगठन निर्माण और रणनीतियों पर चर्चा करेंगी। सितम्बत को प्रदेश कमेटी में विस्तार हुआ है। संगठन विस्तार में दो उपाध्यक्ष, 6 महासचिव, 22 सचिवों और प्रदेश में संगठन का कामकाज देखने के लिए दो संगठन सचिव बनाये गए हैं। महासचिव प्रियंका गांधी के साथ इस बैठक में सभी पदाधिकारियों और कमेटियों के सदस्यों की ठोस जिम्मेदारी, जबाबदेही और टॉस्क तय होंगे।

विकास व उदल को मिली सोशल मीडिया को ऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी

कांग्रेस जिलाध्यक्ष की अगुवाई में किया गया स्वागत

खागा, फतेहपुर । उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया के चेयरपर्सन मोहित पांडेय ने फतेहपुर में सोशल मीडिया में सक्रियता से काम कर रहे विकास मिश्र को जिला कोआर्डिनेटर एवं ऊदल सिंह यादव को कोआर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी है। आज जिला कांग्रेस कमेटी ने दोनों नवनियुक्त कार्यकर्ताओं का गर्म जोशी के साथ स्वागत कि या। जिला ध्यक्ष अखिलेश पांडेय ने दोनों युवाओं को माला पहना कर मुह मीठा कराया। अखिलेश पांडेय ने कहा की जिला कांग्रेस कमेटी नवनियुक्त युवाओं से आशा व अपेक्षा करती है कि ये पार्टी की नीतियों व रीतियों का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से जिले के कोने-कोने तक पहुंचाने का कार्य करेंगे।स्वागत कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष शिवाकांत तिवारी,जिला सचिव उदित अवस्थी,मंसूर आलम,बचई सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

यूथ आइकॉन ने विकास भवन के दो सैकड़ा अधिकारियो व कर्मचारियों को बाटी होम्योपैथिक औषधि

फतेहपुर । बुधवार को दोपहर 12 बजे डॉ सत्यनारायण सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में होमियोपैथिक चिकित्सक यूथ आइकॉन डॉ0 अनुराग श्रीवास्तव द्वारा वैश्विक महामारी कोविड 19 के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु होमियोपैथिक औषधि का वितरण विकास भवन के समस्त अनुभागीय अधिकारी व कर्मचारियों (200) को किया गया। साथ ही डॉ अनुराग श्रीवास्तव ने सभी को विटामिन सी युक्त भोजन,सोशल डिस्टनसिंग व साबुन से हाथ धुलने जैसे बचाव के उपाय बताए।डॉ अनुराग श्रीवास्तव को उनकी सेवाओं हेतु मुख्य विकास अधिकारी श्री सत्यप्रकाश जी,जिला विकास अधिकारी श्री रमेश चंद्रा जी व जिला अर्थ व संख्या अधिकारी के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।इस अवसर पर जिला युवा कल्याण अधिकारी श्री मनोज कुमार यादव,जिला अर्थ व संख्या अधिकारी जोगेंद्र सिंह यादव,उपायुक्त मनरेगा व सभी विभागों के अधिकारी एवं प्रमुख सहयोगी दिलीप श्रीवास्तव जी उपस्थित रहे।

समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में स्वर्गीय एसआरएस बाबूजी की शोक सभा का आयोजन हुआ

जिसमें में जिला अध्यक्ष जय सिंह जयंत के नेतृत्व में महासचिव शब्बीर खान छत्र सभा के जिला अध्यक्ष सलीम काकोरी लखनऊ

जिला उपाध्यक्ष श्रीमती उर्मिला रावत पूर्व नगर उपाध्यक्ष शबनम खान युवा नेता आकाश रावत अन्य साथी उपस्थित कुकर होकर बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना है जिला अध्यक्ष ने कहा कि आज समाजवादी पार्टी ने अपना एक होनहार कार्यकर्ता को दिया है बाबूजी की कमी हमको हमेशा ही महसूस होती रहेगी।

प्राथमिक विद्यालय अस्ती के दिलकश ने मारी बाजी

फतेहपुर । सरकारी स्कूल डॉट इन द्वारा आयोजित मेरा शिक्षक मेरा गौरव प्रतियोगिता में प्राथमिक विद्यालय अस्ती, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश का दिलकश रज़ा विजेता रहा। इस प्रतियोगिता में बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड सहित 7 राज्यों के बच्चों ने भाग लिया था प्रतियोगिता शिक्षक दिवस पर आयोजित की गई थी, जिसमें बच्चों से उनके जीवन में शिक्षक की भूमिका को बताते हुए अधिकतम 3 मिनट का विडियो साझा करने को कहा गया था, प्रतियोगिता का उद्देश्य था कि बच्चों में शिक्षकों के योगदान के प्रति कृत्यज्ञता का भाव जगे, साथ ही शिक्षकों की मेहनत के बारे में समाज को पता चले। दिलकश के विडियो में बेहतर तरीके से प्रस्तुति देने के साथ साथ बिना रुके अच्छे व निश्छल भाव से बोलना मुख्य वजह रही. सरकारी स्कूल डॉट इन

सरकारी स्कूल के बच्चों, शिक्षकों, पूर्व विद्यार्थियों एवं सरकारी स्कूल के लिए कार्य कर रहे लोगों से जुड़ी प्रेरक कहानियों को समाज के बीच में ले जाने के उद्देश्य लिए कार्य कर रही है. सरकारी स्कूल डॉट इन के संस्थापक अभिषेक रंजन ने दिलकश को इस उपलब्धि पर बधाई दी। विडियो कॉल के माध्यम से बात करके उत्साह भी बढ़ाया और इसी तरह सरकारी स्कूल का मान बढ़ाते रहे. अभिषेक ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नही है. जरुरत है उन्हें उचित दिशा देने की, उन्हें मंच मुहैया कराने की. सरकारी स्कूल डॉट इन छुपी हुई प्रतिभाओं को निखरने और एक दुसरे बच्चों से सीखने का भी अवसर देगा. प्रेरक शिक्षिका आसिया जी के नेतृत्व में विद्यालय निरंतर प्रगति की राह पर है, जो बाकियों के लिए प्रेरक है।

ललौली व्यापार मण्डल ने चलाया सदस्यता अभियान

तिरसठ व्यापारियों ने ली सदस्यता

ललौली, फतेहपुर । उद्योग व्यापार मण्डल की सम्बद्ध इकाई ललौली व्यापार मण्डल ने कस्बा ललौली में सदस्यता अभियान जारी करते 63 सदस्य बनाये, जोन प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह, अध्यक्ष मोश जुबैर के नेतृत्व में ललौली व्यापार मण्डल का विस्तार करते संरक्षक पद पर अली अहमद खान को मनोनीत किया गया, अध्यक्ष मो0 जुबैर ने कहा 30 सितम्बर तक कस्बा ललौली में सदस्यताअभियान चलाकर 500 व्यापारियों को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, सदस्य व्यापारियों को संगठन का प्रमाणपत्र व एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। जोन प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह ने कहा ललौली व्यापार मण्डल का विस्तार करने की दिशा में जुड़े हुए कस्बो ग्रामो में संगठन की इकाइयां निर्माणित की जायेगी व व्यापारी एकता को मजबूत करने की दिशा में सार्थक कदम उठाए जायेगे, अवसर पर उद्योग व्यापार मण्डल के संस्थापक/अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा ने ललौली व्यापार मण्डल के पूर्व अध्यक्ष मकबूल खान के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते उनके चित्र पर पुष्पहार पहनाते श्रद्धांजलिअर्पित की, अवसर पर महामंत्री अनिल वर्मा, अली अहमद खान, मो श जुबैर धर्मेन्द्र सिंह, महफूज अहमद खान, एकलाख खान ,मुकेश कुमार निषाद , निजाम मोहम्मद, नफीस खान मकसूद खान महबूब अली उपस्थित रहे, व महरूम मकबूल खान के चित्र पर पुष्प अर्पित करते श्रद्धांजलि अर्पित की।

चीन की चालाकियों पर रहे नजर

चीनी सेना की अक्रामता के जवाब में भारतीय सेना ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. अभी ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना डटी हुई है. ब्लैक टॉप वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) का ऊपरी क्षेत्र है. इसे लेकर अलग-अलग दावे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि यह भारतीय क्षेत्र में है, जबकि इस पर चीन भी दावा करता है. एक-दूसरे पर एलएसी पार करने का आरोप लगाया जा रहा है. अभी पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं है कि किन-किन क्षेत्रों को सेना ने कब्जे में लिया है. मुझे लगता है कि ब्लैक टॉप एरिया में सेना ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. साथ ही उससे नीचे वाले इलाके हेलमेट पर भी सेना काबिज हो चुकी है. इससे भारतीय सेना को रणनीतिक तौर पर बहुत फायदा मिलेगा. अब ऊंचाई से चुशुल एरिया में पूरा पैंगोंग और अक्साई चिन तक के तमाम इलाके दूरबीन से देखे जा सकेंगे. इस घटना के बाद चीन का बौखलाना स्वाभाविक है. पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर चीन का पूरा कब्जा है. वे फिंगर चार से लेकर आठ तक अपने कब्जे में ले चुके हैं, लेकिन दक्षिण पैंगोंग इलाके में भारतीय फौज के एक्शन से उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है. चीनी फौज ने सोमवार को ब्लैक टॉप के नजदीक किसी जगह पर कब्जा कर लिया है. ब्लैक टॉप एरिया में चीनी फौज के 50-100 जवानों की तैनाती कर दी गयी है. उन्होंने अब इस एरिया में नया मोर्चा खोला है. उनकी नजर 10 सितंबर को मॉस्को में होनेवाली दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की वार्ता पर भी टिकी होगी. विदेश मंत्री जयशंकर के साथ चीनी विदेश मंत्री की वार्ता से स्थिति में कुछ बदलाव आ सकता है. बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वार्ता में चीन ने भारतीय सेना पर एलएसी पार कर ब्लैक टॉप पर कब्जा करने का आरोप लगाया. उन्होंने सेना को वापस बुलाने की भी मांग की थी. अब चीन ने वहां अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है. उन्होंने बहुत सोच-समझ कर नया मोर्चा खोलने की चाल खेली है. जब बातचीत होगी, तो यह फैसला हो सकता है कि दोनों तरफ से जहां-जहां दक्षिणी किनारे, चुशुल के इलाके में पोजिशन पकड़ी हैं, वहां से वापस जाएं. यह चीन की तरफ से मांग होगी. भारत भी फिंगर्स, हॉट स्प्रिंग, देपसांग से उनके हटने की शर्त रखेगा. भारत पांच मई से पहले वाली स्थिति को कायम करने को कहेगा. फिलहाल, अभी की स्थिति यह है कि नये मोर्चे खुले हैं. अब तक की बातचीत बेनतीजा रही है, क्योंकि चीनी चाहते हैं कि केवल पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से ही सेना हटायी जाए. एक हफ्ते पहले शुरू हुई बातचीत में उनकी यही मांग थी. चीन ने अभी अरुणाचल प्रदेश में भी तनाव बढ़ाने की कोशिश है. हमें वहां उलझने की बजाय लद्दाख पर फोकस रखना चाहिए. जो नयी स्थिति पैदा हुई है और चीन ने जिस तरह से सोची-समझी चाल चली है. उन्होंने ब्लैक टॉप के नीचे और उसके आसपास अपने 50-60 जवान लगा दिये हैं. अब फौजें एक-दूसरे के काफी करीब आ गयी हैं. अभी तक की बातचीत से किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकल सका है. ऐसे में 10 सितंबर को होनेवाली दोनों विदेश मंत्रियों की वार्ता का हमें इंतजार करना चाहिए. यह भी जरूरी नहीं कि केवल एक बातचीत में ही मामला हल हो जायेगा, लेकिन अगर किसी बात पर सहमति बनती है, तो वह आगे की राह को आसान बना सकती है. हमारे विदेश मंत्री के बयान से दो-तीन बातें स्पष्ट होती हैं. पहली बात कि उन्होंने यह कही है कि जब वे चीन के विदेश मंत्री वांग यी के से वार्ता करेंगे, तो उनकी पहली प्राथमिकता तनाव को कम करने और आपसी सहमति बनाने की होगी. वे केवल ब्लैक टॉप की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे कब्जा किये गये पूरे इलाकों की बात कर रहे हैं. दूसरी बात वह कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में पहले भी 2013 में देपसांग, 2014 में चुमार और 2017 में डोकलाम का मसला बातचीत के जरिये हल हो गया था, तो अभी क्यों नहीं हो सकता? विदेश मंत्री की तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है. उनका कहना है कि भारत-चीन संबंध सीमा पर शांति बहाल करने पर निर्भर हैं. अगर सीमा पर शांति नहीं है, तो भारत-चीन द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं.

इन्हीं बातों पर दोनों नेताओं की बातचीत निर्भर होगी. हमारी शर्त है कि पहले वे सभी जगहों से पीछे हटें, लेकिन वे हाल-फिलहाल की बात करेंगे. वे टालने की कोशिश करेंगे. अगर इस बातचीत में ऐसा कोई संकेत मिलता है कि आगे का रास्ता बंद है (क्योंकि दोनों एक-दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं), तो मुश्किलें थोड़ी बढ़ेंगी. दोनों देशों की सहमति होने पर रूस मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है. यह सबसे महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है, क्योंकि भारत की रूस के साथ अरसे पुरानी घनिष्ठता रही है. अभी चीन और रूस का संबंध सबसे अच्छे दौर में है. कुछ महीने पहले शी जिनपिंग ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने रूस को सबसे करीबी दोस्त बताया था. ऐसे में तनाव को कम करने में रूस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है. मेरा मानना है कि रूस को वार्ता की इस प्रक्रिया में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हालात नाजुक दौर में हैं, मुठभेड़ हो चुकी है, गोली भी चल चुकी है. गलवान में मुठभेड़ के बाद इस हफ्ते गोलियां भी चली हैं. इस बीच मॉस्को में दोनों विदेश मंत्रियों को बैठक भी हो रही है. ऐसे वक्त में अगर रूस आता है, तो उसका काफी असर होगा. अभी जिस तरह से तनाव है, उसमें किसी को यह पता नहीं कि आगे किस तरह के हालात हो सकते हैं. वे घुसपैठ की कोशिश करेंगे, भारतीय फौज उन्हें आने नहीं देगी. आगे मामला और भी गंभीर भी हो सकता है

सम्पादकीय

आपसी लड़ाई से मीडिया को नुकसान

आपने मुर्गों को लड़ते-लड़ाते देखा है. कबूतर-कौव्वे से लेकर शेर-हाथी तक, सब को लड़ते देखा होगा. सामान्यतः घोड़ों को लड़ते कम देखा जाता है. लड़ाई से किसी को क्या मिला है और मिलेगा, लेकिन इन दिनों समाज, देश-दुनिया को शांति सद्भावना का संदेश देने वाले कुछ टीवी मीडिया चौनल, संपादक या स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया पर सक्रिय पूर्व संपादक, पत्रकार और साहित्य-संस्कृतिकर्मी सार्वजनिक रूप से झगड़ ही रहे हैं. राजनीतिक विचारधारा, सत्ता या प्रतिपक्ष से जुड़ाव को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन प्रतियोगिता अथवा निजी नाराजगी में एक-दूसरे को अपराधी, देशद्रोही तक करार देने से क्या किसी को लाभ हो सकेगा?संविधान ने प्रत्येक भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है. सभी समाचार माध्यम उसी अधिकार का लाभ पाते हैं. कुछ नियम-प्रावधान मीडिया के लिए बनते-बदलते रहे हैं. इसलिए, इन दिनों मीडिया के कई दिग्गज, राजनेता, सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग और सामान्य जनता का एक वर्ग मीडिया पर नियंत्रण, लक्ष्मण रेखा की बात कर रहा है. यह बात पिछले पांच दशकों में उठती और दबायी जाती रही है.वर्षों से पत्रकारिता में होने के कारण मैं इन दबावों और प्रयासों को देखता, समझता और झेलता रहा हूं. वर्तमान संदर्भ में, टीवी मीडिया को लेकर गंभीर बहस छिड़ गयी है. वे क्यों सुशांत-रिया प्रकरण या चीन-भारत विवाद या कोरोना महामारी को दिन-रात अतिरंजित ढंग से दिखा रहे हैं? प्रतियोगिता में एक-दूसरे से मार-काट क्यों कर रहे हैं? कौन किस विषय को कितना दिखाए, यह तय कौन करेगा? बात 2006 की है. तब मैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और वरिष्ठ संपादक सच्चिदानंद मूर्ति महासचिव थे. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी. सरकार ने मीडिया के लिए ब्रॉडकास्ट नियामक विधेयक तैयार किया. इससे पहले केवल केबल प्रसारण के नियमन के लिए कुछ नियम-कायदे बने हुए थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े नेता और मंत्री टीवी चौनलों की बढ़ती संख्या और उपभोक्ता अधिकार के बहाने संपूर्ण इलेट्रॉनिक मीडिया को कड़े कानून में बांधना चाहते थे. इस विधेयक में भारत के सभी सरकारी, स्वायत्त और निजी रेडियो, टीवी चौनल के प्रसारण के विषय, लिखी, बोली और दिखायी जाने वाली सामग्री तक पर सरकार की निगरानी का प्रावधान था. मेरे तथा वरिष्ठ संपादक बीजी वर्गीज, कुलदीप नय्यर, मामन मैथ्यू सहित पत्रकारों की नजर में यह प्रस्तावित कानून आपातकाल के सेंसरशिप से भी अधिक खतरनाक था.

इससे पहले प्रिंट माध्यम के लिए बिहार में लाया गया कानून या राजीव गांधी के समय आये प्रेस कानून का एडिटर्स गिल्ड, पत्रकार संगठनों और प्रतिपक्ष ने भी विरोध किया था. इसलिए मनमोहन सरकार के प्रस्तावित विधेयक को कानूनी रूप मिलने से पहले हमने कड़ा विरोध अभियान शुरू कर दिया. गिल्ड के पदाधिकारी के नाते मंत्रियों, सूचना प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार (पूर्व पत्रकार भी) आदि के साथ बैठकें हुईं. इससे सरकार कुछ संशोधन पर विचार करने लगी. संपादकों ने भी वार्ताओं का सिलसिला जारी रखा. इस नये संकट में एडिटर्स गिल्ड ने सुझाव दिया कि किसी सेवा निवृत्त वरिष्ठ न्यायाधीश के मार्गदर्शन में समाचार चौनल के संपादकों का एक सहयोगी संगठन स्वयं अपनी आचार संहिता तय करेगा. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा को यह दायित्व सौंपा गया. इस तरह महीनों के कड़े विरोध, बातचीत और प्रस्तावों से उस विधेयक को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया. एडिटर्स गिल्ड में जब हरि जयसिंह अध्यक्ष और मैं महासचिव था, तब संपादकों के लिए एक आचार संहिता बनायी गयी थी और राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आकर उसे जारी किया था. इसी तर्ज पर, 2007 में टीवी संपादकों, खासकर प्रसारण के लिए नियम, आचार संहिता बनायी गयी. प्रेस परिषद ने भी अनेक नियम औरर आचार संहिता बनायी है, लेकिन कानूनी रूप से उसका दायरा प्रिंट मीडिया तक ही सीमित रहा है. परिषद या संपादकों की आचार संहिताओं में किसी सजा का प्रावधान नहीं है. यानी, इसे अपने जीवन मूल्यों की तरह स्वयं अपनाये जाने की अपेक्षा की जाती है. इस पृष्ठभूमि में आज भी यह प्रश्न है कि प्रकाशन या प्रसारण की सामग्री और प्राथमिकता कौन तय करे? अपराध कथा को प्राथमिकता मिले या राजनीतिक, आर्थिक, मनोरंजक, व्यापारिक, फिल्मी, क्रिकेट या कबड्डी को? कौन कितनी देर क्या दिखाए या बोले, इसे कौन तय करे. हम सब शुचिता के साथ स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं, लेकिन एक-दूसरे को नीचा दिखा कर क्या हम सरकार को प्रसारण नियामक कानून बनवाने के लिए निमंत्रित करना चाहेंगे? सत्ता तो आती-जाती रहती है, कानून हमेशा रहेगा.

भारत के पुराने प्रेस कानून में संशोधन के एक प्रस्ताव पर विचार-विमर्श जारी है. प्रसारण और सोशल मीडिया पर आवाज उठने से सरकार को कहां नुकसान होनेवाला है. हां, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आवाज उठाने वाले ही घायल होंगे और सामान्य नागरिक भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी नियामक व्यवस्था से चुनी गयी सामग्री ही ग्रहण कर सकेंगे. इसलिए, आपसी लड़ाई में भविष्य का ध्यान रख सबको तय करना होगा-आत्म अनुशासन या सरकारी लगाम?

आज के जैसी क्षुद्रताओं से राजनीति को बचाए रखा था गांधी ने

महात्मा गांधी के जीवन को देखें तो हर व्यक्ति की तरह उन्होंने सफलताएं और असफलताएं दोनों ही अर्जित की थीं- अपने सार्वजनिक और निजी जीवन दोनों में। अभी तक के लिखित इतिहास में जितने लोगों को देखा जाये, तो उनमें बापू की कामयाबियां काफी अधिक हैंय और कथित असफलताएं जो भी हैं तो उनका बहुत ही तार्किक और विवेकपूर्ण आधार है। यद्यपि यह भी सच है कि उनकी सफलताओं को नाकामी तथा नाकामियों को अतिरंजना में दिखलाने की कोशिशें होती रहती हैं। जिन मसलों पर दुनियावी अर्थों में वे असफल होते दिखते हैं, उन्हीं पर आश्चर्यजनक ढंग से वे अपनी रूहानी जीत भी दर्ज कर जाते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लेना, जेल चले जाना, अहिंसा आदि उनकी बड़ी नैतिक विजय की श्रेणी में आता है। नैतिकता और मानवीयता की कसौटी पर अपने लगभग सभी उपक्रमों, गतिविधियों, कार्यक्रमों और अभियानों में वे इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या की जाये, अच्छे-खासे कद वाली शख्सियतों को उनके घुटनों तक आना भी मुश्किल है। इसका कारण संभवतरू यही होगा कि कोई भी कार्य करने के पूर्व, विशेषकर सार्वजनिक महत्व के, वे उन्हें अपनी आत्मा के स्तर पर ही पहले टटोल लेते रहे होंगे। जिस कसौटी पर वे सबसे पहले अपने विचारों व कामों को परखते होंगे, संभवतरू वह यही रही होगी कि ये कार्य मानवीय रूप से व्यापक व समग्र हित में हैं या नहीं। किसी भी तरह की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकीर्णताओं और क्षुद्रताओं से वे हमेशा दूर रहे हैं। उनकी वैश्विक और सर्वकालिक स्वीकार्यता का कदाचित यही कारण है। गांधीजी के औदार्य का कारण शायद यही था कि उनके लक्ष्य इतने विराट थे जो विलक्षण उदारता की ही मांग करते थे। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में भारत लौटने के बाद अगले करीब दो साल उन्होंने भारत-भ्रमण किया था। यह उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा इस मायने में रही थी कि वे भारत की जमीनी सच्चाइयों, उसकी विविधताओं, विसंगतियों, विरोधाभासों और शक्तियों से परिचित हुए थे। एक ओर वे इस यात्रा में देश के तल्ख यथार्थ से रूबरू हो रहे थे तो वहीं वे विविध समस्याओं से मुल्क को निजात दिलाने का संकल्प, हौसला तथा अंतर्दृष्टि भी बटोर रहे थे। वे अपने समकालीन स्वतंत्रता संग्राम नेताओं से कई कदम इस मायने में आगे थे कि उन्होंने (कुछेक को छोड़कर) अन्य नेताओं की तरह सीमित सुधारों व इक्का-दुक्का मांगों की बात न कर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से पूर्ण मुक्ति का संघर्ष छेड़ा था।वे जानते थे कि देशवासी अपने सपनों का भारत तभी निर्मित कर सकेंगे जब उसमें विदेशी हुकूमत की दखलंदाजी नहीं होगी। वे यह भी समझते थे कि उन्हें आजादी की इस लड़ाई के दौरान उन तमाम विसंगतियों और अंतर्विरोधों का सामना करना पड़ेगा जिसके दर्शन उन्होंने भारत-भ्रमण के दौरान किये थे। इसलिये उन्होंने हर तरह की संकीर्णताओं को अपनी वैचारिकता और जीवन प्रणाली से निकाल फेंका था। उन्होंने अपनी बाहों का घेरा क्षितिजों तक विस्तृत और हृदय को अंतरिक्ष सा विशाल कर दिया था ताकि उसमें सभी लोग समा सकें। वे जानते थे कि अगर भारत हिंसा, असत्य, लोलुपता, आडंबर, भाषा, जाति, धर्म, प्रांत, असमानता आदि के क्षुद्र और संकीर्ण मसलों में उलझा रहा तो वह अपने वृहत्तर लक्ष्य यानी स्वाधीनता तथा आजादी के बाद देश का प्रमुख उद्देश्य अर्थात उसका पुनरुत्थान कभी नहीं कर सकेगा। देश विभाजन, उससे जनित भीषण दंगे, विस्थापन जैसी तल्खी को भी अगर भारत पचा सका तो वह इसी वैचारिक औदार्य, समन्वय, सौहार्द्र और सहिष्णुता के कारण। अंग्रेजों के जाने के बाद और गांधीजी के भी अवसान के पश्चात कुछ ही समय तक भारत इस उदारता व सहिष्णुता की विरासत का जतन कर सका था-जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री तक। अपनी अन्य कतिपय खूबियों के बावजूद इंदिरा गांधी का कार्यकाल इस दृष्टि से खराब रहा कि तभी भारतीय लोकतंत्र में अनेकानेक बुराइयों ने प्रवेश किया। हमारी संसदीय प्रणाली को राजनैतिक जोड़-तोड़ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से दूषित करने की प्रक्रिया इसी दौरान आरंभ हुई थी। 1977 में जनता पार्टी सरकार का बनना इस मायने में तो महत्वपूर्ण था कि उसने नागरिक स्वतंत्रता की महत्ता को तीन दशकों के बाद फिर से प्रतिपादित किया थाय लेकिन यह भी सच है कि राजनैतिक शुचिता का क्षरण भी यहीं से शुरू हुआ। इसमें किसी एक दल या संगठन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस गंगा को गटर बनाने के लिए सभी राजनैतिक दलों ने अपने घरों से निकलने वाले गंदले पानी की नालियों को इसी के तट पर खोलना शुरू कर दिया था। बाद में कभी मजबूत तो कभी कमजोर, कभी पूर्ण बहुमत की तो कभी गठबंधन की सरकारें आती रहीं-जाती रहीं, लेकिन जो काम निर्विघ्न रूप से होता रहा, वह है सार्वजनिक जीवन और लोकतंत्र को प्रदूषित करने का। पूर्ण बहुमत वाली सरकारों के पास यह सुविधा होती है कि वह पहले से चली आ रही अच्छी या बुरी दोनों ही परम्पराओं में से किसी को भी जारी रख सकती हैं अथवा एकदम अलहदा मार्ग चुन सकती हैं। 2014 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी राजनीति की खराब नजीरों को अपना आदर्श बनाना मुनासिब समझा। शपहले भी ऐसा होता रहा हैश, श्कांग्रेस ने भी तो ऐसा किया थाश- इन वाक्यों को मोदी सरकार ने अपने बचाव के लिये ढाल का इस्तेमाल भी किया और उसमें वेल्यू एडिशन करते हुए पहले के मुकाबले अधिक क्षुद्रताओं के प्रदर्शन का लाईसेंस भी खुद को जारी कर दिया। सत्ता दल भूल गया कि लोकतंत्र सामाजिक व्यवस्था व आत्म परिमार्जन की सतत प्रक्रिया है। गांधीजी के राजनैतिक दर्शन पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि उनका एक विशिष्ट मार्ग था, जिस पर वे अनवरत चलते रहे। उन्होंने अन्य मार्गों का चाहे अस्वीकार किया हो, लेकिन उसके प्रति असम्मान, अपमान या उपहास की भावना उनमें कतई नहीं थी। यहां तक कि जो व्यक्ति, संगठन अथवा विचार आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे, उनकी भी उन्होंने आलोचना नहीं की। इसके उलट, आज की राजनीति का एकमात्र लक्ष्य विपरीत राजनीतिक दर्शनों को ध्वस्त करना ही है। ऐसे वक्त में जब पूरे विश्व के साथ अपना भी देश कोविड-19 की भीषण आपदा से गुजर रहा है, सरकार अपने राजनैतिक विरोधियों को चुन-चुनकर ठिकाने लगा रही है। पिछले कुछ समय से विभिन्न आरोपों में उन्हें सलाखों के पीछे ढकेला जा रहा है।नागरिकता कानून के विरोधियों, मानवाधिकार व सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्र नेताओं और न्यायपालिका में शुचिता के आग्रही वकील (व पहले जज) को जेल भेजने, विरोधी सरकारें गिराने-अपनी बनाने, सरकार के पक्ष में फैसले देने वाले जज को राज्यसभा में पहुंचाने या पीएम-केयर फंड का हिसाब न देने जैसे अलोकतांत्रिक कदम उठाए जा रहे हैं। आपदा को अवसर बनाने की मुहिम के ही अंतर्गत महामारी में लाखों-करोड़ों रुपयों के बेजा इस्तेमाल, करोड़ों इंसानों को भूखे मरने के लिये सड़कों पर छोड़ देने, सत्ताधीशों के मित्रों के घर भरने जैसे काम इसी राजनैतिक क्षुद्रता के उदाहरण हैं। इस कठिन बेला में हमारी राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं सिर चढ़कर बोल रही हैं और उसका शर्मनाक प्रदर्शन किया जा रहा है। नई विदेश नीति के नाम पर अन्य देशों के तानाशाह और दोयम दर्जे के नेताओं को बुलाकर वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा को पर लगाये गये हैं।

न्यायाधीशों का टोटा, न्याय में धोखा

सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक मामलों की पेंडेंसी बढ़ने से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चिंता व्यक्त चुके है। उपराष्ट्रपति नायडू ने सरकार और न्यायपालिका से तेज न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। नायडू ने न्याय की गति तेज और सस्ती व्यवस्था करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। लंबे समय तक मामलों के स्थगन का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि न्याय महंगा हो रहा है ÷न्याय में देरी न्याय से वंचित होना है÷ उपराष्ट्रपति ने टिप्पणी की थी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस व्यक्तिगत, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए निजी हित याचिका नहीं बननी चाहिए। इससे पहले सुर्प्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश को कहना पड़ा कि 18 हजार जज मिलकर 3 करोड़ मुकदमों का भार नहीं उठा सकते। सुप्रीम कोर्ट के सबसे प्रभावशाली मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने कभी कहा था कि '' न्याय व्यवस्था की शक्ति प्रकरणों का निपटारा करने, फैसला देने या किसी दोषी को सजा सुनाने में नहीं है, यह तो आम आदमी का भरोसा और विश्वास जीतने में निहित है। देश के हाईकोर्ट और जनपदीय न्यायालयों में न्यायधीशों की कमी के कारण अदालते लम्बित मुकदमों के बोझ से दबी है। देश में सबसे ज्यादा निराशा जनक स्थिति जनपदीय न्यायालयों की है जबकि यह सर्व विदित है कि आम आदमी के लिए जनपदीय न्यायालय ही न्याय की आस है, आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा नही सकता ऐसे में उसे अमूनन निराशा ही हाथ लगी है। जनपदीय न्यायालय के जो आकड़े सामने आ रहे है उस संदर्भ में अगर भारतीय न्याय व्यवस्था का आकलन करें तो बहुत निराशाजनक दृश्य सामने आता है। इन दिनों लोग यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि कोर्ट के बाहर ही निपटारा कर लो वरना जिंदगी भर पांव घीसते रहोगे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है और मुकदमों का अम्बार लगा है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 59,331 मामले लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में 45,12,800 मामले लंबित हैं, जिनमें से 85 प्रतिश मामले पिछले 1 साल से लंबित हैं। 2,89,96000 से अधिक मामले, देश के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं। इनमे सिविल मामलों की तुलना में आपराधिक मामले अधिक हैं। जो अपने आप में एक बड़ी चिंता है न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने में देरी से, अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 6000 पद खाली पड़े हैं। भारत में प्रति मिलियन आबादी पर केवल 20 न्यायाधीश हैं। इससे पहले, विधि आयोग ने प्रति मिलियन 50 न्यायाधीशों की सिफारिश की थी।देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 414 पद रिक्त हैं। जबकि उच्च न्यायालयों में कुल 1079 न्यायाधीश होने चाहिए। किसी भी अपराध या विवाद में न्याय पाने के लिए हर इंसान न्यायालय का रुख करता है, लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि देश के न्यायालयों में पिछले 10 सालों से विभिन्न मामलों के 37 लाख केस लंबित पड़े हैं। इन मामलों में आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

राष्ट्रीय स्तर पर अदालतों द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी करने वाले राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट में न्याय व्यवस्था पर डराने वाला खुलासा किया। रिपोर्ट के अनुसा भारत में हाईकोर्ट, जिला न्यायालय और तालुका अदालतों के कुल 3.77 करोड़ मामलों में से करीब 37 लाख मामले पिछले 10 सालों से लंबित पड़े हुए हैं। इसमें 28 लाख मामले जिला और तालुका अदालत में हैं। इसी तरह इन अदलातों में 85,141 मामलों में तीन दशक यानी पिछले 30 सालों से कोई फैसला नहीं लिया गया है। यानि जनपदीय न्यायालय की दशा ठीक नही है। वहीं 9.20 लाख मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं।दूसरी तरफ इस डाटा से यह भी पता चला है कि 6.60 लाख से ज्यादा मामले पिछले 20 सालों से लंबित हैं। इसी तरह 1.31 लाख ममले 30 सालों से लंबित है।पूरे भारत में कुल 3.29 करोड़ मामलों में से 8.5 प्रतिशत यानी 28 लाख मामले 10 साल से जिला या तालुका अदालतों में लंबित हैं। इनमें से पांच लाख से अधिक मामले में दो दशक यानी 20 सालों से लंबित चल रहे हैं। देश भर में 25 उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 47 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।इनमें से 19.26 प्रतिशत यानी 9.20 लाख से अधिक मामले 10 से अधिक वर्षों से लंबित हैं और 3.3 प्रतिशत यानी 1.58 लाख मामले 20 सालों से और 46,754 मामले तीन दशक यानी 30 सालों से अधिक समय से लंबित चल रहे हैं। इसमें इलाहबाद उच्च न्यायालय के आकड़े बताते है कि 10 सालों से उच्च न्यायालयों में लंबित 9.20 लाख मामलों में से 2.76 लाख मामले इलाहबाद उच्च न्यायालय में लंबित हैं। इसी तरह 20 साल वाले मामलों में से 55 प्रतिशत और 30 साल वालों में से 86 प्रतिशत लंबित है।देश की जिला अदालतों में तीन करोड़ से ज्यादा मुकदमें लंबित हैं और इनके निस्तारण की जिम्मेदारी अभी मात्र 18144 जजों के कंधों पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जजों के कुल मंजूर 23597 पदों में से 5453 खाली हैं। इनमें भी आधे से ज्यादा रिक्तियां केवल पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है जहां जिला अदालतों में जजों के 1404 पद खाली हैं। देश के पांच राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान में आधे से ज्यादा 3244 पद रिक्त है। वैसे ही जनसंख्या के हिसाब से पहले ही जजों की संख्या कम है। अभी 10 लाख की आबादी पर करीब 20 जज हैं। जबकि 1987 में विधि आयोग ने 10 लाख की आबादी पर 50 जजों की जरूरत बताई थी। मुकदमों का सबसे ज्यादा बोझ निचली अदालतों पर रहता है।

पहली अदालत होने के कारण सबसे ज्यादा वक्त भी यहीं लगता है क्योंकि यहां गवाहियां, साक्ष्य, ट्रायल होते हैं। निचली अदालतों में राज्य वार जजों की संख्या पर निगाह डाली जाए तो कुल 36 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की जिला अदालतों में जजों के कुल 23597 पद मंजूर हैं लेकिन सिर्फ 18144 पदों पर ही जज हैं बाकी के 5453 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुल 3416 पद मंजूर हैं, जिसमें मात्र 2012 जज ही काम कर रहे हैं। बाकी के 1404 पद खाली हैं। बिहार में मंजूर पद 1847 हैं, जिसमें 695 खाली हैं। मध्य प्रदेश में 2021 पद मंजूर हैं जिसमें 517 रिक्त हैं। गुजरात में 1506 पदों में 321 खाली हैं और राजस्थान में कुल मंजूर 1428 में 307 खाली हैं। ऐसे में इन पांच राज्यों की जिला अदालतों में कुल लंबित मुकदमों के आकड बताते है कि देश भर की अदालतों मे लंबित कुल 34038211 मुकदमों में लगभग आधे 16073542 इन्हीं पांच राज्यों में लंबित हैं। अगर उत्तर प्रदेश में जजों की संख्या ज्यादा है और रिक्तियां भी ज्यादा हैं तो लंबित मुकदमों में उसकी हिस्सेदारी भी पांच राज्यों में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में कुल 8109410 मुकदमें लंबित हैं, जिसमें 6326615 क्रिमनल केस है जबकि 1782795 दीवानी हैं। उत्तर प्रदेश के बाद जजों के सबसे ज्यादा पद बिहार में खाली हैं तो लंबित मुकदमों में भी बिहार दूसरे स्थान पर है जहां निचली अदालतों में कुल 3075599 मुकदमें लंबित हैं जिसमें से 2664439 क्रिमनल केस हैं और 411160 दीवानी केस हैं। मध्यप्रदेश में कुल 1513077 केस लंबित हैं जिसमें 1178392 क्रिमनल केस हैं। इसी तरह राजस्थान में कुल 1710686 मुकदमें लंबित हैं जिसमें 1248521 क्रिमनल केस हैं और गुजरात में कुल 1664767 मुकदमें लंबित हैं जिसमें 1233822 क्रिमनल केस हैं बाकी के दीवानी मुकदमें हैं। 2018-19 के आर्थिक सर्वे में कहा गया था कि कि निचली अदालत का एक जज एक साल में तकरीबन 746 केस निपटाता है। मुकदमा निपटाने की ये दर 89 फीसद है। उसमें कहा गया था कि पांच साल में मुकदमों का बैकलाग खत्म करने के लिए 8151 जजों की और जरूरत होगी। लेकिन कोरोना के चलते पिछले करीब छह महीने से मामले पर विधिवत सुनवाई नहीं हो पाई इसके कारण देश की हर अदालत में मुकदमें लम्बित हुए है।

सार समाचार .....

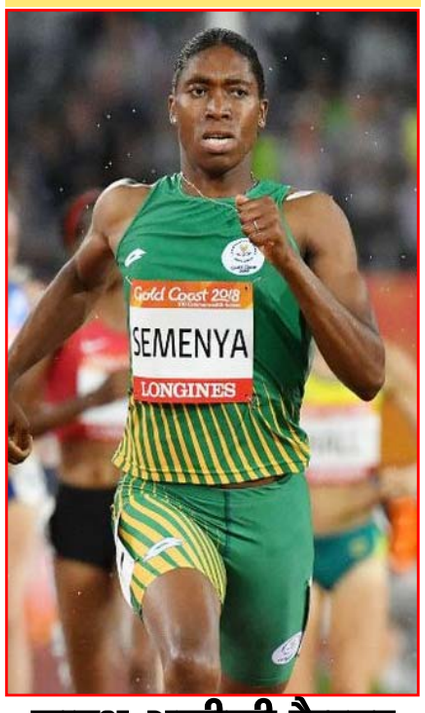

साउथ अफ्रीकी कैस्टर सेमेन्या केस हारीं

नई दिल्ली **एजेंसी।** साउथ अफ्रीका की ओलिंपिक 800 मीटर चैम्पियन कैस्टर सेमेन्या अब महिलाओं के साथ नहीं दौड़ सकेंगी। वे मंगलवार को स्विट्जरलैंड की सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई हैं। कोर्ट ने उनके शरीर में मौजूद मेल हार्मोन कम करने के लिए इलाज कराने के आदेश दिए हैं। पिछले साल द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (खेल पंचाट) ने सेमेन्या को हार्मोन कम कराने के आदेश दिए थे। खेल पंचाट ने कहा था कि सेमेन्या को शरीर में रिसने वाले मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन को दवा लेकर कम कराना होगा। सेमेन्या ने इस फैसले के खिलाफ स्विस कोर्ट में अपील दायर की थी, जो अब खारिज हो गई है।

मैं खुद को नहीं बदलूंगी- सेमेन्या

सेमेन्या ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। उन्हें पता है कि यदि वे हार्मोन कम नहीं करेंगी, तो अगले साल होने वाले टोक्यो ओलिंपिक में शामिल नहीं हो सकेंगी। इसके बावजूद उन्होंने कहा, ''मैं इस तरह के नियम को लेकर सहमत नहीं हूं। मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स के ड्रग्स (हार्मोन कम करने की दवा) लेने के आदेश को नहीं मानती। मैं जो भी हूं, ठीक हूं। खुद को नहीं बदलूंगी।''

सेमेन्या के शरीर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा ज्यादा

सेमेन्या ओलिंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2-2 और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 3 गोल्ड जीत चुकी हैं। कैस्टर 2009 में पहली बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में दौड़ी थीं। इसके बाद आईएएएफ ने कैस्टर का जेंडर टेस्ट कराया था। टेस्ट में पता चला कि उनके शरीर में रिसने वाले टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा है।

पुरुष कैटेगरी में दौड़ने की मंजूरी मिली थी

टेस्ट रिपोर्ट के बाद फेडरेशन ने कैस्टर के वुमन कैटेगरी में दौड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फेडरेशन ने कहा था कि अगर सेमेन्या रनिंग करना चाहती हैं, तो उन्हें पुरुष कैटेगरी में दौड़ना होगा या फिर उनको मेडिकल प्रोसेस के जरिए शरीर का टी-लेवल (टेस्टोस्टेरॉन लेवल) कम कराना होगा।

भगवान का दिया हुआ शरीर है, हार्मोन कम करने की दवा नहीं लूंगी

सेमेन्या ने खेल पंचाट के आदेश के बाद कहा था, ''मुझे भगवान पर भरोसा है। ये जिंदगी भगवान की दी हुई है। जिंदगी में क्या होना है, ये भी वही तय करेगा। जब वो चाहेगा, मेरा करिअर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं चाह रहा, तब तक कोई इंसान मुझे रोक नहीं सकता। मेरा ये शरीर भी भगवान का दिया है, मैं किसी के भी कहने पर अपने शरीर के किसी भी हार्मोन को कम कराने के लिए कोई दवा नहीं लूंगी। हरगिज नहीं।''

पुरुषों के शरीर में होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन

टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन है। यह पुरुषों के शरीर में ही होता है। इसकी मात्रा 300 से 1000 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच हो सकती है। टी-लेवल से मूड, शारीरिक और मानसिक सक्रियता तय होती है। महिलाओं में इसकी मात्रा 20 से 30 होती है। सेमेन्या के शरीर में यह टी-लेवल बढ़कर 400 से 500 के बीच पहुंच गया है। इसी वजह से वे अन्य महिला एथलीट्स से जेनेटिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत हैं।

सौरभ गांगुली आईपीएल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दुबई रवाना

बेंगलुरू एजेंसी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली 19 सितंबर से जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग की तैयारियों का जायजा लेने बुधवार को दुबई के लिए रवाना हुए। भारत में बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए इस टी20 टूर्नमेंट को संयुक्त अरब अमीरात में कराया जा रहा है, जिसके शुरुआती मैच में गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नै सुपरकिंग्स से होगा। गांगुली ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी फोटो के साथ पोस्ट किया, छह महीने में मेरी पहली फ्लाइट आईपीएल के लिए दुबई जाना होगा...जिंदगी बदल जाती है। गांगुली इस फोटो में मास्क और चेहरे की शील्ड पहने हुए थे, जो महामारी के दौरान उड़ान के वक्त मानक परिचालन प्रक्रिया का हिस्सा है। आईपीएल के चेयरमैन बृजेश पटेल उन अहम अधिकारियों में शामिल हैं, जो पहले ही दुबई जा चुके हैं।

100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर

हरभजन ने आईपीएल के 160 मैचों में 150 विकेट लिए, 829 रन भी बनाए

सीएसके के 2 खिलाड़ी के अलावा 11 स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं

न्यूयॉर्क | एजेंसी।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है। उन्होंने यह उपलब्धि नेशंस कप में स्वीडन के खिलाफ हासिल की। यह मैच पुर्तगाल ने 2-0 जीता। दोनों गोल रोनाल्डो ने 45वें और 72वें मिनट में किए।

पुर्तगाल का अगला मैच 10 अक्टूबर को फ्रांस से होगा। रोनाल्डो 165 मैच में 101 इंटरनेशनल गोल के साथ दुनिया के दूसरे और यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस लिस्ट में ईरान के अली देई 149 मैच में सबसे ज्यादा 109 इंटरनेशनल गोल के साथ टॉप पर काबिज हैं।

चोट के कारण लीग का पहला मैच नहीं खेल सके थे

इससे पहले पैर के अंगूठे में चोट के कारण रोनाल्डो नेशंस लीग में क्रोएशिया के खिलाफ मैच नहीं खेल सके थे। इससे पहले उन्होंने अपना पिछला मैच 17 नवंबर को यूरो कप के क्वालिफाइंग मैच में लक्समबर्ग के खिलाफ खेला था।

फ्री किक के जरिए रोनाल्डो ने 100वां गोल पूरा किया

रोनाल्डो ने स्वाडन क खिलाफ मच म ब्रेक से पहले फ्री किक को गोल में तब्दील कर अपना और टीम का खाता खोला। इसके साथ ही उन्होंने अपना 100वां भी गोल पूरा किया। वहीं उन्होंने मैच के 73वें मिनट में पेनाल्टी एरिया से गोल मारकर दूसरा गोल किया।

अगला टारगेट 109 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ना है- रोनाल्डो

रोनाल्डो ने कहा, ''मैं 100 गोल का टारगेट हासिल करने में सफल रहा। अब मेरा लक्ष्य 109 गोल के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना है, जो ईरान के अली देई के नाम दर्ज है। मैं स्टेप बाई स्टेप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। मैं जुनूनी नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि रिकॉर्ड नेचुरल तरीके से आते हैं।''

यूरोप में नवंबर के बाद कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुए

यूरोप में कोरोना के कारण पिछले नंवबर के बाद कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं हुए हैं। हालांकि ला लिगा, चैम्पियंस लीग और यूरोपा लीग खेले गए हैं। वहीं, 2020 यूरोपा फुटबॉल लीग को भी अगले साल के लिए रद कर दिया गया है।

रोनाल्डो ने 2004 में डेब्यू किया था

रोनाल्डो ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच ग्रीस के खिलाफ 12 जून 2004 को खेला था। इसमें अपना पहला इंटरनेशनल गोल किया था। जबकि अली देई ने अपने देश के लिए पहला इंटरनेशनल मैच 25 जून 1993 को ताइपे के खिलाफ खेला था। अली ने पहले ही मैच में 3 गोल किए थे। उन्होंने टीम को 6-0 से जीत दिलाई थी। जबकि उन्होंने अपना अंतिम इंटरनेशनल मैच 1 मार्च 2006 को कोस्टा रिका के खिलाफ खेला था।

भारत के सुनील छेत्री 10वें नंबर पर

सबसे ज्यादा इंटरनेशन गोल के मामले में भारत के सुनील छेत्री 10वें नंबर पर हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 115 मैच में 72 गोल दागे हैं। इस मामले में वे अर्जेंटीना के लियोनल मेसी से काफी आगे हैं। मेसी इस लिस्ट में 70 गोल के साथ 17वें नंबर पर हैं। इसके लिए उन्होंने 138 मैच खेले हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लिश टीम को क्लीन स्वीप से रोका

लाहौर , एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को पांच विकेट से हराया। इस जीत की बदौलत उसने मेजबानों को सीरीज क्लीन स्वीप करने से रोक लिया। यह सीरीज 2-1 पर खत्म हुई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले तो इंग्लिश टीम को 145/6 के सामान्य स्कोर पर रोका। उसके बाद 19.3 ओवर में पांच विकेट पर 146 रन बना डाले। कप्तान एरॉन फिंच और शॉन मार्श ने 39-39 रनों की उपयोगी पारी खेली। राशिद ने तीन विकेट लिए। इंग्लैंड से बेयरिस्टो (55) ने अर्धशतक जमाया। जंपा को दो विकेट मिले। इंग्लैंड ने सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था। पहले टी-20 में भी 2 रन से जीता था। इसी के साथ इंग्लैंड की 2 साल के भीतर लगातार सातवीं टी-20 सीरीज है, जिसमें वो नहीं हारा। इस दौरान उसने 6 सीरीज जीती। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ पिछले महीने हुई टी-20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही। दोनों देशों के बीच अब तक 19 टी-20 हुए हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने 10 और इंग्लैंड ने 8 जीते हैं। एक मैच बेनतीजा रहा।

1960 ओलिंपिक के बाद से हर बार बजट से औसतन 172 प्रतिशत ज्यादा खर्च हुआ, अब बदलाव की जरूरत

नई दिल्ली , एजेंसी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में दावा किया गया है कि इंटरनेशनल ओलिंपिक कमेटी (आईओसी) द्वारा बड़े बदलाव नहीं किए जाने की वजह से पिछले कुछ समय में गेम्स में बजट से कहीं ज्यादा खर्च हो रहे हैं। 1960 के बाद से खेलों पर बजट से औसतन 172 प्रतिशत ज्यादा खर्च हुए हैं। टोक्यो ओलिंपिक पर अभी तक 13 बिलियन डॉलर (करीब 96 हजार करोड़ रु) अधिक खर्च हुए हैं, जो शुरुआती बजट से कहीं ज्यादा है। कोरोना की वजह से खेल को एक साल आगे बढ़ाया गया है। आईओसी द्वारा बिडिंग प्रक्रिया के पूरे होने से पहले ही 2024 और 2028 के ओलिंपिक का आयोजन पेरिस और लॉस एंजिल्स को दे दिया गया था।

अभी के समय में बदलाव की जरूरत

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेजर प्रोग्राम मैनेजमेंट के प्रोफेसर और अध्यक्ष बेंट फ्लावजर्ज ने कहा कि अभी के समय में बदलाव की जरूरत है। पिछले 25 सालों में आईओसी ने इन्वेंशन और इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया है। क्योंकि उन्हें इवेंट के लिए खर्च नहीं देना पड़ता। मेजबान शहर को खेलों के खर्च की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। आईओसी की तरफ से उन्हें 1 बिलियन डॉलर (करीब 7 हजार करोड़) की राशि मिलती है।

आईओसी का बर्ताव लापरवाही भरा

फ्लावजर्ज ने कहा कि इस मुद्दे पर आईओसी का बर्ताव लापरवाही भरा रहा है। दूसरी तरफ ओलिंपिक कमेटी का कहना है कि उन्होंने रिसर्च नहीं देखी है। उनकी तरफ से बयान जारी कर कहा गया, रिसर्चर्स ने पिछले कुछ वर्षों में आईओसी से किसी भी तरह के डेटा का अनुरोध नहीं किया है।

बल्लेबाज सैफ हसन और कंडीशनिंग कोच का टेस्ट पॉजिटिव

नई दिल्ली | एजेंसी।

कोरोनावायरस की चपेट में अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी आ गई है। उसके युवा बल्लेबाज सैफ हसन के साथ स्ट्रैंथ और कंडीशनिंग कोच निक ली का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। दोनों सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। बांग्लादेश बोर्ड ने यह जानकारी मंगलवार को दी। बांग्लादेश को श्रीलंका दौरा अक्टूबर-नवंबर में निर्धारित है। इसके लिए टीम 27 सितंबर को रवाना होगी। इसकी तैयारी को लेकर राजधानी ढाका में बायो-सिक्योर माहौल में ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है।

हसन ने इसी साल टेस्ट में डेब्यू किया

बांग्लादेश बोर्ड के फिजिशियन डॉ. देबाशीष चौधरी ने क्रिकेट वेबसाइट ईएसपीएल क्रिकइंफो से बात की। उन्होंने कहा, ''हमारी टीम निक ली के मामले में जांच कर रही है कि वे अभी-अभी संक्रमित हुए हैं, या पहले से बीमार हैं।''

वहीं, हसन ने इसी साल टेस्ट में डेब्यू किया था। उन्होंने फरवरी में पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट खेला था।

आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे बांग्लादेशी क्रिकेटर

बांग्लादेश बोर्ड ने मुस्तफिजूर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) खेलने के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) नहीं दिया। श्रीलंका दौरे के कारण बोर्ड ने यह फैसला लिया। इस बांग्लादेशी लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर को आईपीएल की दो टीमों कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और डिफेंडिंग चैम्पियन मुंबई इंडियंस से खेलने का ऑफर मिला था।

2 ग्रैंड स्लैम विजेता नाओमी ओसाका दूसरी बार सेमीफाइनल में

नई दिल्ली , एजेंसी।

दो ग्रैंड स्लैम विजेता जापान की नाओमी ओसाका ने टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में वुमन्स सिंगल्स के सेमीफाइनल में दूसरी बार जगह बनाई है। इनके अलावा अमेरिकी जेनिफर ब्रेडी पहली बार सुपर-4 में पहुंच गईं। यह ग्रैंड स्लैम कोरोनावायरस के बीच बायो-सिक्योर माहौल में 13 सितंबर तक खेला जाएगा।

वर्ल्ड नंबर-9 ओसाका ने अमेरिका की शेल्बी रोजर्स को 6-3, 6-4 से हराया है। वहीं, जेनिफर ने कजाखस्तान की यूलिया पुतिंत्सेवा को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। ज्वेरेव पहली बार किसी भी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में

वहीं, वर्ल्ड नंबर-7 जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। यह उनका किसी भी ग्रैंड स्लैम का पहला सेमीफाइनल होगा। उन्होंने क्वार्टरफाइनल में क्रोएशिया के बोर्ना कोरिच को 1-6, 7-6, 7-6, 6-3 से हराया। ज्वेरेव अब तक कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीत सके हैं।

ओसाका 2018 में यूएस ओपन जीत चुकीं

दुनिया की नंबर-9 ओसाका दो ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। उन्होंने 2018 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन ही जीता था। इसके बाद अगले साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन पर कब्जा जमाया था। यह उनका किसी भी ग्रैंड स्लैम का तीसरा सेमीफाइनल होगा।

रायूडू को वर्ल्ड कप से बाहर करने से लेकर धोनी को फेयरवेल मैच न देना

दिल्ली | एजेंसी।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति के पूर्व मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद को अपने कई फैसलों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने बतौर चीफ सिलेक्टर अपने तीन सबसे मुश्किल फैसलों का जिक्र किया है। प्रसाद ने बताया कि आखिर अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे कौन से फैसले से थे जिन्हें लेने में उन्हें खासी मुश्किलें पेश आईं। इसमें से एक 2019 विश्व कप में अंबाती रायूडू को नहीं शामिल करना भी एक रहा। प्रसाद ने उन फैसलों का जिक्र किया जिनके लिए उनकी काफी आलोचना हुई। रायूडू को वर्ल्ड कप टीम में न चुनना, करुण नायर को इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में तिहरा शतक लगाने के बाद भी पर्याप्त मौके न देना और महेंद्र सिंह धोनी को एक फेयरवेल मैच न दे पाना उनके करियर के सबसे कठिन फैसले कहे जाते हैं। स्पोर्ट्सकीड़ा से बात करते हुए प्रसाद ने बताया कि आखिर क्यों नायर टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए।, करुण नायर ने तिहरा शतक लगाया था। इसके बाद वह तीन चार टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके बाद अगले एक साल तक भारत ए के अगले एक-दो दौरों पर भी वह असफल रहे। इसके बाद भी हमने उन्हें 2018 में इंग्लैंड दौरे पर भेजा लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। 2018-19 का उनका रणजी सीजन भी अच्छा नहीं रहा। इसी वजह से वह दौड़ में पिछड़ गए। अंबाती रायूडू को विश्व कप 2019 के लिए टीम में शामिल न करने पर भी प्रसाद ने अपनी राय रखी। हालांकि उन्होंने कोई एक निश्चित कारण नहीं बताया पर कहा कि किसी के मन में रायूडू के खिलाफ कोई बात नहीं थी। प्रसाद के इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी। भारतीय टीम टूर्नमेंट में नंबर चार पर बिना किसी स्थायी बल्लेबाज के उतरी थी। एमएसके प्रसाद ने कहा, मुझे लगता है कि हमने रायुडू को इस पोजीशन (नंबर चार) के लिए तैयार किया था और आखिर में उनके स्थान पर भेजा गया। इससे मुझे भी थोड़ा दुख हुआ। लेकिन इसके पीछे एक कारण था... इसमें कोई भी निजी नहीं था। सब कुछ टीम और टीम के हित में लिया गया फैसला था। एमएसके प्रसाद ही टीम के मुख्य चयनकर्ता थे जब रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को सीमित ओवरों की टीम से बाहर किया था। भारतीय टीम जब 2017 के चैंपियंस ट्रोफी के फाइनल में पाकिस्तान से हारी थी इसके बाद इन दोनों को सीमित ओवरों की टीम से बाहर कर दिया गया था। हालांकि जडेजा ने अपनी जगह वापस बना ली है लेकिन अश्विन ने जुलाई 2017 के बाद से भारत के लिए सीमित ओवरों के क्रिकेट में नहीं खेला है। प्रसाद ने कहा, चैंपियंस ट्रोफी के बाद हमने अश्विन और जडेजा को ब्रेक देने का फैसला किया। हमने सोचा कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को मौका दिया और उन दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया। उस समय अश्विन और जडेजा आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर की पायदान पर थे। हम उनके साथ ही आगे बढ़ने का विचार कर रहे थे। यह विश्व कप से पहले एक तैयारी के तौर पर आजमाया गया था। नतीजा यह हुआ कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल सीमित ओवरों के प्रारूप में स्थायी हो गए। एमएसके प्रसाद ने बीसीसीआई की सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन के तौर पर सितंबर 2016 से मार्च 2020 तक काम किया। उनके स्थान पर टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर सुनील जोशी के पदभार संभाला।

इंग्लिश बल्लेबाज ने कहा- अभी विराट कोहली के साथ तुलना ठीक नहीं, 50 मैच के बाद उनके आसपास आ सकता हूं

नई दिल्ली | एजेंसी।

इंग्लिश बल्लेबाज डेविड मालन (33) ने कहा है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ उनकी तुलना करना ठीक नहीं है। वे कोहली के आसपास भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 50 मैच खेलने के बाद हो सकता है कि वे कोहली के आसपास पहुंच सकते हैं। मालन इंग्लैंड के लिए तीसरे नंबर बल्लेबाजी करते हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 16 टी-20 में 48.71 की औसत से 682 रन बनाए हैं। इसमें 101 रन की पारी भी शामिल है। मलान ने 1 वनडे मैच खेला है। जबकि 15 टेस्ट मैच में 27.85 की औसत से 724 रन बनाए हैं।

3 साल पहले डेब्यू किया था

मलान ने इंग्लैंड के लिए जून 2017 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 से डेब्यू किया था। उनको जेसन रॉय और बेन स्टोक्स की गैरहाजिरी में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नियमित रूप से खेलने का मौका मिला।

50 गेम खेलने के बाद तुलना करना सही

मलान ने क्रिकेट वेबसाइट ईएसपीएन क्रिकइंफो से कहा, ''मुझे यह जानना पसंद है कि मैं टीम के लिए कहां खड़ा हूं। यही कारण है कि मैंने कहा कि जब आप सीरीज में खेलते हैं तो आपको पता होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं।''

स्थायी रूप से जगह बना पाना अपने हाथ में नहीं

मलान ने कहा कि टीम में स्थायी रूप से जगह बना पाना, उनके हाथ में नहीं है। वे अभी ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहते हैं। पिछले 4-5 सालों में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। उनका मानना है कि कोई भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इंग्लैंड के लिए लगातार खेलना और जीतना होगा।

जेसन रॉय और बेन स्टोक्स कभी भी वापस आ सकते हैं

उन्होंने कहा, ''मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि जेसन और स्टोक्स जैसे लोग किसी भी समय वापस आ सकते हैं। मेरा काम यह है कि जितने भी मौके हैं, उनका फायदा उठाते हुए इयोन मोर्गन और सिलेक्टर्स पर दबाव बनाऊं।''

मुंबई एयरपोर्ट पर करणी सेना और शिवसेना आमने सामने, चकमा देकर निकल गई कंगना रनौत

अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई पहुंच चुकी है. हालांकि उन्हें मुंबई पहुंचने के साथ ही भारी विरोध का सामना करना पड़ा. वो एयरपोर्ट से भारी विरोध से बचते हुए निकल गयी हैं. एयरपोर्ट में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कंगना को काला झंडा दिखाया. हालांकि कंगना के समर्थन में करणी सेना भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे. एयरपोर्ट पर कंगना के समर्थक और विरोध करने वाले आमने-सामने आ गये. कंगना के विरोध में शिवसेना कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं. इस बीच बंबई हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के घर पर बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है. बीएमसी ने आज सुबह कंगना के घर को बुलडोजर से गिराना शुरू कर दिया था. अभिनेत्री कंगना रनौत आज चंडीगढ़ से 12 बजे मुंबई के लिए फ्लाइट लीं और करीब 3 बते दोपहर मुंबई पहुंचीं. मुंबई पहुंचने से पहले ही कंगना के विरोध में शिवसेना कार्यकर्ता जमे हुए थे. हालांकि कंगना को केन्द्र सरकार द्वारा ल् श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. इधर, मुंबई निकलने से पहले कंगना रनौत ने एक मंदिर में पूजा-अर्चना की है. बीएमसी ने जारी किया नोटिस- कंगना रनौत के मुंबई आने की खबर के बीच बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस के बाहर दूसरी बार नोटिस चस्पा कर दिया है. बीएमसी के अधिकारी कंगना के ऑफिस

पर हथौड़े चलाने की तैयारी में भी है. कोरेंटिन कर सकती है बीएमसी- कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने पर सबसे अधिक संभावनाएं कोरेंटिन करने की है. महाराष्ट्र सरकार अब भी बाहर से आने वाले लोगों को कोरेंटिन कर रही है. ऐसे में कंगना को भी कोरेंटिन किया जा सकता है. वहीं कंगना कोरेंटिन किए जाने को लेकर पहले ही आशंका जता चुकी है. कंगना ने किया ट्वीट- वहीं मुंबई आने से पहले अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट किया है. कंगना ने ट्वीट कर लिखा, श्रानी लक्ष्मीबाई के साहस,शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है. दुख की बात यह है मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है मै रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूँगी ना डरूंगी, ना झुकूँगी. गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी. सुरक्षा में 11 कमांडर- वहीं इससे पहले, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि 9 सितंबर को कंगना का मुंबई जाने का कार्यक्रम है. वहां इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि सुरक्षा की जरूरत पड़े. हिमाचल में सुरक्षा कड़ी करने के हमने डीजीपी को आदेश दिए हैं. गृह मंत्रालय द्वारा वाई प्लस सुरक्षा के मद्देनजर 11 आरपीएफ कमांडो तैनात किए जा चुके हैं . उन्होंने आगे कहा कि कंगना से मेरी बात हुई उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने मुझे मोरल सपोर्ट दिया खासकर तब, जब मैं परेशानी के दौर में हूं. मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं. मुंबई चार-पांच दिनों के लिए जाना होगा वापिस हिमाचल आने पर बात करेंगे.

बीएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर कंगना के ऑफिस पर चलाया बुलडोजर

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बांद्रा स्थित ऑफिस को कथित रूप से कई अनधिकृत संशोधनों ध् एक्सटेंशन के कारण तोड़ना शुरू कर दिया। बीएमसी एच-वेस्ट वार्ड की एक टीम पुलिस के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची। इससे पहले, बीएमसी ने ऑफिस के बाहर एक नोटिस चिपकाया, जिसमें कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी द्वारा मंगलवार के नोटिस के मद्देनजर दायर जवाब को खारिज कर दिया गया था, जिसमें बीएमसी ने उनके कार्यालय में चल रहे निर्माण में कई उल्लंघनों का जिक्र किया था। यह कदम सोशल मीडिया पर कंगना और महाराष्ट्र के कुछ राजनेताओं के बीच साझा किए गए छिड़ी जुबानी जंग के बाद सामने अया है। बीएमसी के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट थे कि (अवैध) निर्माण किए जा रहे थे और अभिनेत्री बीएमसी कानूनों के अनुसार इसके लिए अनुमति अनुमोदन,स्वीकृति प्रदान करने में विफल रही थी।नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई कि अभिनेत्री को जुर्माना के अलावा, न्यूनतम एक महीने की कैद और एक साल की जेल की सजा तक हो सकती है।

निया शर्मा से लेकर शिविन नारंग तक इन सितारों ने बिग बॉस 14 का ऑफर ठुकराया

टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 14'को लेकर कई नई डिटेल्स सामने आ रही हैं। बिग बॉस के इस सीजन के लिए कई बड़े सितारों को मेकर्स ने अपोर्च किया है लेकिन शो का हिस्सा उन सेलेब्स ने बनने से साफ इंकार कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि किस-किस ने इस शो का ऑफर ठुकाया है।

ये कलाकार नहीं बनना चाहते 'बिग बॉस 14' का हिस्सा

निया शर्मा

टीवी की मशहूर अभिनेत्री निया शर्मा ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है। खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया का खिताब भी निया शर्मा ने अपने नाम किया है। बता दें कि बिग बॉस के 12वें सीजन में निया शर्मा को ऑफर हुआ था लेकिन निया ने इस शो के हिस्सा बनने से इंकार कर दिया था।

सुरभि ज्योति

नागिन फेम सुरभि ज्योति को भी बिग बॉस के घर कैद होने का ऑफर दिया गया था लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे घर में वह लंबे समय तक कैद नहीं हो सकती।

शिविन नारंग

बेहद फेम शिविन नारंग को बिग बॉस के 14वें सीजन ऑफर हुआ था लेकिन यह ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया था।

जेनिफर विंगेट

बेहद फेम एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट को भी बिग बॉस 14 का ऑफर मिला था लेकिन उन्होंने हिस्सा बनने से इंकार कर दिया। हालांकि मेकर्स ने शो का हिस्सा बनने के लिए 3 करोड़ रूपए भी जेनिफर को ऑफर किए लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया।

पर्ल वी पूरी

बिग बॉस 14 के मेकर्स ने टीवी एक्टर पर्ल वी पूरी को शो का हिस्सा बनने के लिए 5 करोड़ों रुपए ऑफर किए। लेकिन उन्होंने करोड़ों रूपए भी ठुकारा दिए।

एली गोनी

सलमान खान के शो बिग बॉस का ऑफर ये है मोहब्बतें एक्टर एली गोनी को दिया गया था। लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। जबकि इस शो का हिस्सा एली गोनी की खास दोस्त जैस्मिन भसीन बन सकती हैं।

अनु मलिक

बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार और सिंगर अनु मलिक को भी बिग बॉस का ऑफर हुआ है लेकिन उन्होंने इसका हिस्सा बनने से इंकार कर दिया।

सारा गुरपाल

बिग बॉस के मेकर्स ने एक्ट्रेस-मॉडल सारा गुरपाल को ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया।

अभिनेता दिलीप ताहिल का कंगना रनौत पर फूटा गुस्सा,कहा-दूसरों को बोलने से पहले खुद करवाए ड्रग टेस्ट

बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर अपने विवादित बयानों की वजह से खूब सुर्खियों में छाई हुई हैं। दरअसल दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से कंगना रनौत ने एक बार फिर से बॉलीवुड में नेपोटिजम के मुद्दे उठाया था। वहीं दूसरी ओर सुशांत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद कंगना ने अपना बयान दिया था कि बॉलीवुड के 99 प्रतिशत लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। बता दें कि कंगना ड्रग्स को लेकर कई बॉलीवुड सितारों को निशाने पर लिया उन्होंने यहां तक कहा कि रणवीर सिंह,रणबीर कपूर,विकी कौशल और अयान मुखर्जी जैसे लोग कोकीन का सेवन करते हैं और इनका ब्लड टेस्ट भी जरूर होना चाहिए।

अब कंगना के इतने सारे स्टार्स पर आरोप लगा देने के बाद मशहूर अभिनेता दिलीप ताहिल ने अपना इस पर जोर का रिएक्शन दिया है। एक निजी चौनल की रिपोर्ट के अनुसार दिलीप ताहिल ने कंगना के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अपने किसी भी साथ में काम करने वाले कलाकार के बारे में इस तरह की बातें बोलने से पहले कंगना रनौत को सबसे पहले तो खुद का ब्लड टेस्ट एक बार जरूर करा लेना चाहिए। इतना ही नहीं दिलीप ताहिल ने यह भी कहा कि कंगना का बयान स्पष्ट नहीं है। आगे एक्टर कहते हैं फिल्म जगत में केवल वही नजर आता है जो दुनिया में हो रहा है और यह नहीं पता कि ऐसे आरोप लगाने के पीछे कंगना का आखिरकार क्या उद्देश्य है। दिलीप ताहिल ने कंगना के पक्ष में बात करते हुए कहा कि कंगना खुद सेल्फमेड टॉप स्टार हैं। इंडस्ट्री में एक महिला को जो भी चौलेंज फेस करने पड़ते हैं बावजूद उसके कंगना ने बॉलीवुड में अपना सफल स्थान कायम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कंगना इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि फिल्म इंडस्ट्री में सभी को अफसर मिलते हैं,मगर अब उनके बयान बहुत ज्यादा भ्रामक होते जा रहे हैं। क्योंकि एक दो-बार तो वह पॉइंट की बातें कहती हैं,परंतु अब ऐसा मालूम होता है कि सबकुछ सोच-समझकर ही किया जा रहा है। आगे अभिनेता ने कहा कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं मुश्किल बल्कि बिजनेस,मीडिया और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को मौका तक नहीं मिल पाते हैं साथ ही उनका शोषण भी किया जा रहा है और इन क्षेत्रों और मुद्दों पर तो सबसे पहले बातचीत होनी चाहिए। याद दिला दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत 9 सितंबर को मुंबई वापस लौट रही हैं जिसके बाद उनके यहां आने के बाद उनसे जुड़े विवादों के और बढने का अंदाजा लगाया जा रहा है।

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने अपनी फीमेल पेट डॉग डायना का ऐसे मनाया चौथा जन्मदिन

बॉलीवुड एक्टेस प्रियंका चोपड़ा को कुत्तों के प्रति लगाव बहुत है। प्रियंका के तीन पेट डॉग हैं जिनसे वह बेहद प्यार करती हैं। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा की फीमेल डॉग डायना का आज चौथा जन्मदिन है जिसे वह बहुत उत्साहित होकर मना रही हैं। प्रियंका ने एक खूबसूरत पोस्ट डायना के लिए उसके जन्मदिन पर साझा की है। डायना के जन्मदिन पर प्रियंका ने एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है और उसमें डायना के अब तक के हसीन पलों को दिखाया गया है। डायना मस्ती व खेलती हुई इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डायना के साथ प्रियंका और निक दोनों ने फेटो पोस्ट की और उसे चौथे जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां दीं। इससे पहले पांडा नाम का एक नया कुत्ता प्रियंका और निक लाए थे। प्रियंका ने अपने इन्हीं पालतू जानवरों के साथ पूरे कोरोना काल में समय बिताया है और खूब मस्ती करती हुई नजर आई हैं। सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा सक्रिय रहती हैं। प्रियंका अपने फैन्स के साथ अपने जीवन की हर छोटी से बड़ी बातें साझा करती रहती हैं। हालांकि अमेरिका में प्रियंका अपने परिवार के साथ रह रही हैं लेकिन बॉलीवुड दुनिया की हर खबर की जानकारी उनके पास होती है। सोनू सूद पिछले कई महीनों से प्रवासी मजदूर और असहाय लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए इन कामों के लिए प्रियंका ने सोनू सूद की जमकर तारीफ की। इस समय पति निक जोनस और अपने पालतू डॉग्स के साथ कोरोना समय में प्रियंका समय बिताती नजर आती है।

तेलुगु टीवी अभिनेत्री कोंडापल्ली श्रावणी ने की खुदकुशी

तेलुगु टेलीविजन अभिनेत्री कोंडापल्ली श्रावणी ने हैदराबाद में अपने घर पर कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी है। 26 साल की श्रावणी मंगलवार को मधुरनगर स्थित अपने आवास पर फांसी पर लटकी पाई गईं। परिवार के सदस्यों ने कहा कि वह अपने बेडरूम में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें लगा कि वह नहा रही हैं लेकिन जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आई तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा और देखा कि वो लटकी हुई हैं। वे उन्हें अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को परीक्षण के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार ने आरोप लगाया है कि श्रावणी ने अपने पूर्व प्रेमी देवराज रेड्डी के उत्पीड़न से परेशान होकर यह कदम उठाया है। पुलिस ने कहा है कि परिवार ने उसके खिलाफ कुछ दिन पहले मामला दर्ज कराया था और उन्होंने श्रावणी को उसके साथ घूमने को लेकर चेतावनी भी दी थी। एस.आर. नगर सर्कल के इंस्पेक्टर नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि देवराज के साथ घूमने को लेकर मंगलवार की देर रात श्रावणी की अपनी मां और भाई के साथ बहस हुई थी। इसके बाद वह अपने कमरे में गई और खुद को फांसी लगा ली पुलिस ने देवराज को गिरफ्तार करने के लिए आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर में एक टीम भेजी है। सर्कल इंस्पेक्टर ने कहा, च्चूंकि श्रावणी का परिवार उस पर आरोप लगा रहा है, इसलिए हम उसे गिरफ्तार करेंगे और पूछताछ करेंगे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि देवराज को जून में श्रावणी द्वारा शिकायत करने के बाद गिरफ्तार किया गया था, इसमें कहा गया था कि वह श्रावणी से शादी करने के लिए उसे परेशान कर रहा था। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि देवराज के खिलाफ शिकायत करने के बाद भी पुलिस कार्रवाई करने में विफल रही है। बता दें कि देवराज कुछ महीने पहले टिक-टॉक के माध्यम से अभिनेत्री के संपर्क में आए थे और फिर दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। श्रावणी के परिवार ने कहा है कि देवराज ने उसे पैसे के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। वह उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दे रहा था। लिहाजा परिवार ने देवराज को 1 लाख रुपये गूगल पे के माध्यम से दिए। हालांकि कथित रूप से वह पैसे लेने के बाद भी उसे परेशान करता रहा, लिहाजा उन्होंने उसके खिलाफ एस.आर.नगर थाने में 22 जून को शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि शिकायत में वीडियो और तस्वीरों का कोई जिक्र नहीं था।बता दें कि श्रावणी ने मनासु ममता और मौनरागम जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में अभिनय किया था।

सोनू सूद के फैन ने सिम कार्ड पर बनाई एक्टर की पेंटिंग,तो शख्स को मिला ऐसा मजेदार रिप्लाई

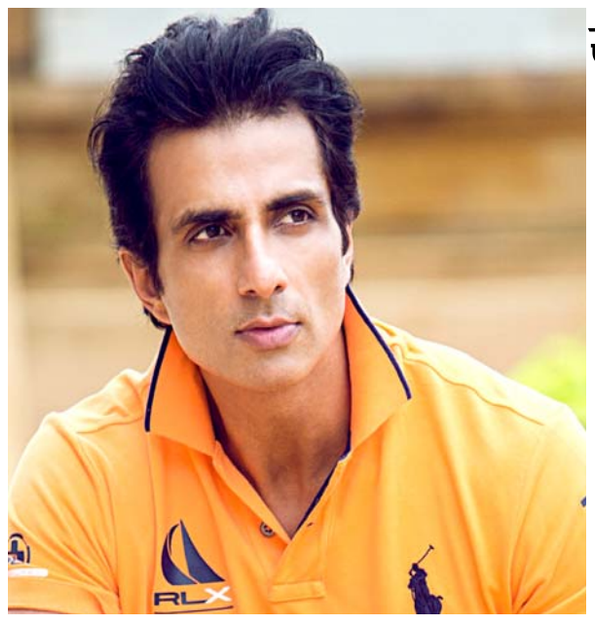

कोरोना काल में गरीबों का मसीहा बने फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सभी लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली है,अभी तक भी सोन सूद से जो उनसे किसी तरह की मदद मांगता है वह कभी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। कोरोना महामारी के बीच जिस तरह अभिनेता लोगों की मदद करने के लिए आगे आएं अब उस वक्त को शायद ही एक पल के लिए भी कोई भूला सकता है। वैसे सोनू सूद के अब देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब चर्चे हैं तभी तो अब उनके फैंस विदेशों से उन्हें याद कर रहे हैं। हाल ही में सोनू सूद के एक फैन ने ट्विटर पर उन्हें टैग कर उनके लिए एक बेहद शानदार पेटिंग बनाई है। सोमिन नाम के एक ट्विटर यूजर ने सिम कार्ड में सोनू सूद की हूबहू तस्वीर बना दी है,जिस पर अब एक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शानदार तरीके से रिप्लाई भी दिया है।

कंचन उजाला
हिंदी दैनिक

स्वामी नमोकंचन कार्पोरेट सर्विसेस (एल.एल.पी) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक कंचन सोलंकी द्वारा उमाकान्ती ऑफसेट प्रेस, ग्राम डेहवा पोस्ट मोहनलाल गंज लखनऊ से मुद्रित एवं 61/18 चुटकी भण्डार हुसैनगंज लखनऊ से प्रकाशित।

संपादक- कंचन सोलंकी

TITLE CODE- UPHIN48974

Mob: 8896925119, 9695670357
Email: kanchansolanki397@gmail.com

नोटः समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारो एवं लेखों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नही। समस्त विवादो का निस्तारण लखनऊ न्यायालय के अधीन होगा।